अब्दुल रहमान अंतुले ई. टी. सी. ईटीसी।

वी.

आर. एस. नायक और ए. एन. आर., ई. टी. सी. ईटीसी।

10 दिसंबर, 1991

1

[के. एन. सिंह, सी. जे., पी. बी. सावंत, एन. एम. कासलीवाल,

बी.

बी. पी. जे. ई. वी. एन. रेड्डी और जी. एन. रे, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:अनुच्छेद 21-त्वरित सुनवाई का अधिकार-चाहे वह अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत प्रक्रिया का हिस्सा हो-चाहे वह जांच, जांच, परीक्षण, अपील, संशोधन और पुनः सुनवाई का व्यापक हो-क्या कार्यवाही के समापन के लिए कोई बाहरी सीमा निर्धारित की जा सकती है।

त्वरित सुनवाई की मांग करने या उस पर जोर देने में अभियुक्त की विफलता को उचित ठहराना और समझाना कि क्या इसके परिणामस्वरूप इनकार हो सकता है-राहत-कार्यवाही पर रोक लगाने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए पहले उच्च न्यायालय के न्यायालय में मांगी जाएगी।डी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 309 और 482-अभियुक्त का त्वरित सुनवाई का अधिकार कार्यवाहियों के समापन में अत्यधिक देरी-परिचर परिस्थितियों और प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए न्यायालय का विवेक-दिशानिर्देश ई हैं

मुकदमा दायर किया।दो रिट याचिकाओं में से पहली में याचिकाकर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।प्रथम प्रतिवादी 1981 से याचिकाकर्ता के खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों सहित विभिन्न अपराधों के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए कदम उठा रहा है।शुरू में वे राज्यपाल से मंजूरी के अभाव में सफल नहीं हुए।राज्यपाल से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी ने आपराधिक कानून संशोधन के तहत बनाए गए विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई

च

↓

याचिकाकर्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अधिनियम, 1952।मुख्य आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने कुछ न्यासों के लिए धन एकत्र करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।विशेष न्यायाधीश ने शिकायत का संज्ञान लिया और प्रक्रिया जारी की। याचिकाकर्ता विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुआ और विशेष न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के संबंध में आपत्तियां उठाई।चूंकि विशेष न्यायाधीश ने आपत्तियों को खारिज कर दिया, इसलिए याचिकाकर्ता ने टी.आपराधिक संशोधन के माध्यम से उच्च न्यायालय।इस बीच राज्य सरकार ने उक्त मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश को नामित करते हुए एक अधिसूचना जारी की।आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया गया था।

जी.

कोई नहीं।

▾ 326

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

विशेष न्यायाधीश के समक्ष, याचिकाकर्ता ने नई आपत्तियाँ उठाईं कि

क.

उनके खिलाफ आरोप निराधार थे और इसलिए भी कि वे एम. एल. ए. थे, राज्यपाल की मंजूरी के बिना संज्ञान लेना वैध नहीं था। उन्होंने सुनवाई स्थगित करने का भी अनुरोध किया।विशेष न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना मामला नहीं चल सकता है और तदनुसार उन्होंने आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया।इसके बाद प्रथम प्रतिवादी बी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इस न्यायालय का विचार था कि एम. एल. ए. आई. पी. सी. की धारा 21 के अर्थ में 'लोक सेवक' नहीं था और इसलिए मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता था।मामले के इस दृष्टिकोण में, इसने विशेष न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि मुकदमे को उस चरण से आगे बढ़ना चाहिए जिस पर याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त किया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा दायर संबंधित अपील में, इस न्यायालय ने इस विचार की पुष्टि की कि निजी शिकायत पर भी संज्ञान लिया जा सकता है।

डी.

इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, विशेष मामला था

उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपा गया।याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि मामले की सुनवाई केवल आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 के तहत सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस तरह के मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।यह और अन्य संबंधित आपत्तियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।याचिकाकर्ता ने

ई.

उक्त आदेश के खिलाफ अपील की गई और इस अदालत ने इसे खारिज कर दिया।बाद में, कार्यवाही को उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने 21 आरोप बनाए लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तावित 22 अन्य शीर्षों के तहत आरोप तय करने से इनकार कर दिया।प्रथम प्रत्यर्थी ने उक्त आदेश के खिलाफ इस न्यायालय का पक्ष लिया, जहाँ तक कि उसने उसे तैयार करने से इनकार कर दिया।

च

कुछ शुल्क।इस अदालत ने इसकी अनुमति दी थी।इसके बाद, कार्यवाही को उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने 79 आरोप बनाए और मुकदमे को आगे बढ़ाया।कई गवाहों से पूछताछ की गई।उस स्तर पर याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।पी. सी. याचिकाकर्ता द्वारा आरोप तय करने के आदेश और एक अन्य आदेश के खिलाफ दो एसएलपी भी दायर किए गए थे।आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने 1984 में जारी इस न्यायालय के निर्देशों के बाद लिए गए उक्त विशेष मामले में सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।इसके परिणामस्वरूप फर्स्ट रेस्पॉन डेंट द्वारा एक वर्ष की अवधि में दर्ज किए गए अपने साक्ष्य को व्यावहारिक रूप से पूरा करने के बाद कार्यवाही अनिश्चित हो गई।मामला अब एच आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 के अनुसार विशेष अदालत में आगे बढ़ना था।चूंकि इस 327 में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक

:

मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में दर्ज साक्ष्य को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मानने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन भी वर्तमान मामलों का हिस्सा है।इस बीच, एक अधिवक्ता ने उक्त विशेष मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश नामित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बी न्यायालय के निर्देश को देखते हुए राज्य सरकार के लिए एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति को अधिसूचित करना आवश्यक था।तदनुसार राज्य सरकार

एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और 16.9.91 पर विशेष न्यायाधीश ने पक्षों को आगे के कदमों के लिए उनके सामने उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए।इसके बाद

जमानती वारंट जारी किए गए और याचिकाकर्ता को जमानत दे दी गई।

एस.

दूसरी रिट याचिका में याचिकाकर्ता, एक वकील को तत्कालीन रेल मंत्री की हत्या के मामले में 6.7.1975 पर गिरफ्तार किया गया था।

और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की हत्या का प्रयास।पहले मामले में, 10.11.1975 पर आरोप पत्र दायर किया गया था।दूसरे मामले में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया और चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।हालाँकि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील में जमानत प्राप्त की, लेकिन उसे रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि वह दूसरे मामले में भी शामिल था।आई. डी. 1 पर, इस अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत दे दी और मामले को पटना से दिल्ली स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया।याचिकाकर्ता को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया और जनवरी, 1981 में आरोप तय किए गए।बड़ी मात्रा में साक्ष्य और कई मध्यस्थ वार्ताकार पक्षकारों को देखते हुए मुकदमे में लगभग 5 साल लग गए।अभियोजन पक्ष ने कुछ गवाहों को बरी कर दिया।याचिकाकर्ता ने बरी किए गए कुछ गवाहों को तलब करने के लिए एक आवेदन दायर किया। निचली अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया, याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मुकदमे में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी; रोक जारी है।

डी.

ई.

च

दोनों याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने के लिए वर्तमान रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी कि त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

दूसरी बात, अर्थात।, पटना में बिहार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बिहार के जी राज्य द्वारा आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी गई है।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे त्वरित सुनवाई के हकदार हैं, जिसका अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है।

संविधानः त्वरित सुनवाई के अधिकार को सार्थक बनाने के लिए, सक्षम और प्रभावी लागू करने के लिए, एक बाहरी सीमा होनी चाहिए जिससे आगे एच 328

कार्यवाही जारी रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।

2

इस न्यायालय ने पहले ही मामले में ऐसी बाहरी सीमा निर्धारित कर दी है

16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सामान्य अनुप्रयोग के लिए एक समान नियम विकसित करना होगा।

अपीलार्थी-राज्य ने तर्क दिया कि किसी भी कार्यवाही को देरी के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, और अदालतें हमेशा निचली अदालत को उपयुक्त निर्देश जारी करके त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर सकती हैं, जिसमें अदालत में स्थानांतरण के आदेश शामिल हैं, जहां शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सकता है; कि जबकि अमेरिका में 'त्वरित सुनवाई का अधिकार' व्यक्त और अयोग्य है, भारत में यह केवल न्याय और निष्पक्षता का एक घटक है; कि अनुच्छेद 21 को निर्देश सिद्धांतों का मजाक बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है और

ग समानता खंड; कि किसी भी बाहरी सीमा को निर्धारित करना न तो अनुमेय है और न ही संभव है और इस तरह के न्यायिक विधान की गारंटी देने वाला कोई पूर्ववर्ती नहीं था।

प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से, यह तर्क दिया गया था कि इस न्यायालय को संबंधित कोई मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करने चाहिए

डी.

त्वरित सुनवाई का अधिकार, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता में इस संबंध में पर्याप्त प्रावधान हैं और धारा 482 पर्याप्त उपचार के रूप में काम कर सकती है। और यह कि याचिकाकर्ता स्वयं मामलों की सुनवाई में देरी के लिए जिम्मेदार थे और वे इसकी शिकायत नहीं कर सकते थे

त्वरित सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन।

ई.

मामलों को खारिज करते हुए, यह न्यायालय,

अवधारित 1.1 त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जैसा कि अमेरिकी संविधान के छठे संशोधन में स्पष्ट रूप से इस अधिकार को मान्यता दी गई है।ए. के. गोपालन के मामले में यह चूक और अभिनिर्णय बताता है कि जब तक गोपालन इस क्षेत्र में थे, तब तक इस अधिकार का अनुच्छेद 21 से बहने वाले मौलिक अधिकार के रूप में दावा या मान्यता क्यों नहीं दी गई थी।एक बार जब आर. सी. कूपर में गोपालन का शासन समाप्त हो गया और इसका सिद्धांत मेनका गांधी में अनुच्छेद 21 तक विस्तारित हो गया, तो अनुच्छेद 21 गोपालन में रखे गए प्रतिबंधात्मक अर्थ से मुक्त हो गया।यह एक ऐसी शक्ति और जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए आया जिसका अब तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, और जी के बाद की न्यायिक घोषणाओं के साथ, त्वरित मुकदमे के अधिकार को अनुच्छेद 21 में निहित के रूप में मान्यता दी गई और अब यह अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का गठन करता है।[354 - एच; 355 ए-सी] 1.2।संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया अभियुक्त पर तेजी से मुकदमा चलाने का अधिकार देती है।त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का अधिकार है।तथ्य यह है कि एक त्वरित मुकदमा भी है

1 329

ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक

जनहित में या यह कि यह सामाजिक हित की भी सेवा करता है, ए को अभियुक्त का अधिकार नहीं बनाता है।यह सभी संबंधित लोगों के हित में है कि अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का जल्द से जल्द निर्धारण किया जाए।

परिस्थितियों में संभव है।[377 - डी] 1.3।अनुच्छेद 21 से आने वाले त्वरित सुनवाई के अधिकार में सभी शामिल हैं

चरण, अर्थात् जाँच, जाँच, विचारण, अपील पुनरीक्षण बी और पुनः विचारण का चरण।[377 - ई]

आर. सी. कॉपर बनामभारत संघ, [1970] एससीआर 564; मेनका गांधी बनाम।भारत संघ, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 592; हुसैनारा खातून (आई) बनाम।बिहार राज्य, [1979] 3 एस. सी. आर. 169; हुसैनारा खातून (II) बनाम।बिहार राज्य, [1979] 3 एस. सी. आर. 393; हुसैनारा खातून (III) v.बिहार राज्य, [1979] 3 एससीआर 532; सी बिहार राज्य बनाम। उमा शंकर केत्रीवाल और अन्य।, [1981] 2 एस. सी. आर. 402; खदरा पहाड़िया बनाम।बिहार राज्य, [1983] 2 एस. सी. सी. 104; महाराष्ट्र राज्य बनामचंपालाल पुंजाजी शाह, [1982] 1 एस. सी. आर. 299; टी. वी. वथीस्वरन बनामतमिलनाडु राज्य,

आई.

[1983] 2 एस. सी. आर. 348; एस. गुइन और अन्य।वी.ग्रिंडलाया बैंक लिमिटेड, [1985] सप्लीमेंट।3 एस. सी. आर. 818; शीला बार्से और अन्य।वी.भारत संघ और अन्य।, [1986] 3 एससीआर 562; डी

रघुबीर सिंह और अन्य।वी.बिहार राज्य, [1986] 3 एससीआर 802; राकेश सक्सेना बनाम।राज्य, [1987] 1 एससीआर 173; श्रीनिवास गोपाल बनाम।केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, [1988] पूरक।(1) एस. सी. आर. 477; टी. जे. स्टीफन और अन्य।वी.पारले बॉटलिंग कं. (पी) लिमिटेड और अन्य।, [1988] 3 एससीआर 296; ए. पी. बनाम राज्यपी. वी. पवित्रन, [1990] 2 एस. सी. सी. 340, पर भरोसा किया।

ए. के. गोपालन बनाममद्रास राज्य, [1950] एस. सी. आर. 88, संदर्भित।2. वास्तव में, त्वरित सुनवाई का अधिकार अंतर्निहित है

इस देश का वैधानिक कानून।धारा 309 Cr.P.C की उप-धारा 1 और 2. और धारा 344 Cr.P.C की उप-धारा 1 और 1 ए. को धारा 482 सी. आर. के साथ पढ़ा जाना है।पी. सी. जो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाता है।च

बाद वाला प्रावधान उच्च न्यायालय की पारित करने की शक्ति को मान्यता देता है।

"न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा" उचित आदेश।कई मामलों में, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय ने कार्यवाही को छोड़ने या बंद करने का निर्देश दिया है जहां

ऐसी कार्यवाहियाँ न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं या जहाँ न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसी कार्रवाई की माँग की जाती है।इस प्रकार जी अनुच्छेद 21 के अलावा भी, इस देश में अदालतें आपराधिक मामलों में अनुचित देरी से अवगत रही हैं और जहां भी अत्यधिक देरी हुई या जहां कार्यवाही बहुत लंबे समय से लंबित थी और आगे की किसी भी कार्यवाही को दमनकारी और अनुचित माना गया था, उन्हें उचित आदेश देकर समाप्त कर दिया गया था।[365 बी-एच; 366-ए, ई]

' एच 330

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनचंदर वी।हैदराबाद राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 524; वीरभद्र बनाम।

क.

रामास्वामी नायकर, [1959] एस. सी. आर. 1211; चज्जू राम बनाम।राधे श्याम, [1971] पूरक।एससीआर 172; यू. पी. राज्य बनामकपिल देव शुक्ला, [1972] 3 एससीसी 504, पर भरोसा किया।

3.1 .संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।इस देश में मुख्य प्रक्रियात्मक कानून दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 है।कई अन्य अधिनियमों में भी कई प्रक्रियात्मक प्रावधान हैं।मेनका गांधी के बाद, इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि अनुच्छेद 21 में 'कानून' को अनुच्छेद 14 और 19 में निहित तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी का जवाब देना है, अर्थात, इस तरह के कानून को एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करनी चाहिए जो निष्पक्ष, उचित और न्यायपूर्ण हो।केवल तभी, यह अनुच्छेद 21 के आदेश के अनुरूप होगा। वास्तव में, जहां भी आवश्यक हो, ऐसी निष्पक्षता को ऐसे कानून में पढ़ा जाना चाहिए।यह नहीं कहा जा सकता है कि एक कानून जो किसी आपराधिक मामले की उचित रूप से त्वरित जांच, परीक्षण और निष्कर्ष का प्रावधान नहीं करता है, वह निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित है।यह अभियुक्त के साथ-साथ समाज दोनों के हित में है कि एक आपराधिक मामला

डी जल्द ही समाप्त हो गया।यदि अभियुक्त दोषी है, तो उसे ऐसा घोषित किया जाना चाहिए।समाज!हित दोषी को दंडित करने और निर्दोष को दोषमुक्त करने में निहित है, लेकिन इस निर्णय पर उचित प्रेषण के साथ पहुंचा जाना चाहिए-उचित

मामले की सभी परिस्थितियों में।चूँकि यह अभियुक्त है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है और वह व्यक्ति भी है जिसका जीवन और/या स्वतंत्रता खतरे में है, इसलिए यह कहना उचित है कि उसे तेजी से मुकदमा चलाने का अधिकार है।तदनुसार, ई यह राज्य का दायित्व है कि वह इस अधिकार का सम्मान करे और इसे सुनिश्चित करे।[374 डी-एच] 3.2।अपराध के लिए आरोपित होने का तथ्य ही चिंता का विषय है।यह 1 के बीच व्यक्ति की प्रतिष्ठा और स्थिति को प्रभावित करता है

सहकर्मियों और समाज में।यह चिंता और खर्च का कारण है।अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो यह अधिक होता है।यदि यह एक गंभीर अपराध है, तो व्यक्ति अपना अपराध खो सकता है।

च

जीवन, स्वतंत्रता, करियर और वह सब जो वह संजोए रखता है।दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान सुसंगत हैं और वास्तव में इस धारा को स्पष्ट करते हैं।

शिष्य।वे शीघ्र जाँच और त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई का प्रावधान करते हैं।[374 - एच; 375-ए, बी]

माधेश्वर सिंह बनाम।बिहार राज्य, ए. आई. आर 1986 पटना 324; राज्य

जी.

वी.मकसूदम सिंह, ए. आई. आर. 1986 पटना 38, ने मंजूरी दी।

बार्कर वी.यूनिंगो, (33 लॉयर्स एडन। 101); स्ट्रंक बनाम।संयुक्त राज्य अमेरिका, (37

लॉयर्स एडन।2nd, 56); बेल v.अभियोजन निदेशक, जमैका, (1985) 2 एईआर 585; संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम।हॉक, (88 लॉयर्स एडन। 2nd, 640), संदर्भित।

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक

331

4.1 .त्वरित सुनवाई के अधिकार में निहित चिंताओं में कहा गया है कि अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले अनावश्यक या अनावश्यक रूप से लंबे समय तक कारावास में नहीं रखा जाना चाहिए; चिंता, चिंता, खर्च और उसके व्यवसाय और शांति में गड़बड़ी, जो एक अनुचित रूप से लंबी जांच के परिणामस्वरूप होती है।

जांच या मुकदमा न्यूनतम होना चाहिए और अनुचित देरी से बचना चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त की अपना बचाव करने की क्षमता में कमी आ सकती है, चाहे वह मृत्यु, गुमशुदगी या बी गवाहों की अनुपलब्धता के कारण हो या अन्यथा।[377 एफ-एच)।

4.2 .यह आमतौर पर आरोपी होता है जो प्रो में देरी करने में रुचि रखता है।

आहार।हालाँकि, किसी भी पक्ष द्वारा अपने अधिकारों और हितों को सही साबित करने के लिए सद्भावना से की गई कार्यवाही को देरी की रणनीति के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसी कार्यवाही को आगे बढ़ाने में लगने वाले समय को देरी के रूप में गिना जा सकता है।केवल गणना के दिन में देरी करने के लिए की गई तुच्छ कार्यवाही या कार्यवाही को सद्भावना से की गई कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है।केवल यह तथ्य कि एक आवेदन/याचिका स्वीकार की जाती है और एक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन का आदेश अपने आप में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कार्यवाही तुच्छ नहीं है।बहुत बार ये ठहराव पूर्व-पक्ष डी पर प्राप्त किए जाते हैं।

प्रतिनिधित्व।[378 ए-डी]

4.3 .यह निर्धारित करते समय कि क्या अनुचित देरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी को सभी परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें अपराध की प्रकृति, अभियुक्त और गवाहों की संख्या, संबंधित न्यायालय का कार्य-भार, प्रचलित स्थानीय स्थितियां आदि शामिल हैं-जिसे प्रणालीगत देरी कहा जाता है।त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है और राज्य में न्यायपालिका भी शामिल है।ऐसे मामलों में पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण के बजाय यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।[378 डी-ई]

4.4 .प्रत्येक विलम्ब आवश्यक रूप से अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता है।एफ हालांकि, अत्यधिक लंबी देरी को पूर्वाग्रह के अनुमानित प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है।इस संदर्भ में अभियुक्तों को कैद करने का तथ्य भी प्रासंगिक होगा।अभियोजन पक्ष को उत्पीड़न नहीं बनने दिया जाना चाहिए।लेकिन अभियोजन कब उत्पीड़न बन जाता है, यह फिर से किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।[378 - एफ]

जी.

यू. एस. वी. इवेल, (15 लॉयर्स एडन।2 एन. डी., 627, संदर्भित।

5. आपराधिक कार्यवाही के समापन के लिए कोई समय सारिणी निर्धारित करना संभव नहीं है।अपराध की प्रकृति, अभियुक्तों की संख्या, गवाहों की संख्या, विशेष अदालत में काम का बोझ, संचार के साधन और कई अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

एच 332 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट · [1991] एसयूपीपी।3 एस. सी. आर. ए. अपनी प्रकृति के कुछ अपराध जैसे षड्यंत्र के मामले, दुरूपयोग स्वामित्व के मामले, गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी, राजद्रोह, लोक सेवकों द्वारा अवैध भाग की संपत्ति का अधिग्रहण, उच्च लोक सेवकों और उच्च लोक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और मुकदमे में अधिक समय लगता है।फिर, प्रत्येक न्यायालय, जिले, क्षेत्र और राज्य में काम का बोझ अलग-अलग होता है।कई स्थानों पर आवश्यक संख्या में अदालतें उपलब्ध नहीं हैं।बी कुछ स्थानों पर, बार के सदस्यों द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़तालें कार्य-अनुसूची में हस्तक्षेप करती हैं।इस प्रकार, चीजों की प्रकृति और वर्तमान परिस्थितियों में एक समय सीमा तय करना संभव नहीं है, जिसके बाद आपराधिक कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी रेखा खींचने से इनकार कर दिया है और न ही यूनाइटेड किंगडम में ऐसी रेखा खींची गई है।जहाँ कहीं भी त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत हो

मिले।

ग को बनाया जाता है, एक अदालत को मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करना होता है और एक निर्णय पर पहुंचना होता है कि क्या वास्तव में कार्यवाही अन्यायपूर्ण रूप से लंबी अवधि से लंबित है।कई मामलों में, आरोपी स्वयं देरी के लिए जिम्मेदार हो सकता है।ऐसे मामलों में उसे अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।इसलिए दांडिक कार्यवाहियों के समापन के लिए एक बाहरी समय सीमा खोजना या निर्धारित करना न तो उचित है और न ही व्यवहार्य है।त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा करना भी आवश्यक नहीं है।

[375 जी-एच; 376 ए-सी]

6. किसी मामले में, यदि कोई अभियुक्त त्वरित सुनवाई की मांग करता है और फिर भी उसे वह नहीं दिया जाता है, तो यह उसके पक्ष में एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।लेकिन वह इस आधार पर त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने से वंचित नहीं है कि उसने त्वरित सुनवाई के लिए नहीं कहा या उस पर जोर नहीं दिया।[376 - एफ]7. आम तौर पर, उल्लंघन से बहने वाला एकमात्र परिणाम

त्वरित सुनवाई का अधिकार, जैसा भी मामला हो, आरोपों और/या दोषसिद्धि को रद्द करना है।लेकिन यह एकमात्र आदेश नहीं है जो अदालत के लिए खुला है।किसी मामले में अपराध की प्रकृति सहित तथ्य ऐसे हो सकते हैं कि आरोपों को रद्द किया जा सके।

च

न्याय के हित में नहीं होना चाहिए।आखिरकार, प्रत्येक अपराध, विशेष रूप से आर्थिक अपराध, जो सरकारी अधिकारियों और खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित हैं -

समाज के खिलाफ अपराध।यह वास्तव में समाज है-राज्य जो अपराधी पर मुकदमा चलाता है।ऐसे मामलों में, जहां आरोपों/दोषसिद्धि को रद्द करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है, अदालत के लिए ऐसे उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए खुला होगा जो मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत माने जा सकते हैं।

[376 जी-एच; 377-ए, बी]8.अंततः, अदालत को कई प्रासंगिक कारकों-'संतुलन परीक्षण' या 'संतुलन प्रक्रिया'-को संतुलित और तौलना होता है और प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करना होता है कि क्या किसी मामले में त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार किया गया है।[379 - सी]

एच.

1 333

ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक

9. त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार करने और उस कारण से राहत ए के आधार पर आपत्ति को पहले उच्च न्यायालय को संबोधित किया जाना चाहिए।भले ही उच्च न्यायालय इस तरह की याचिका पर विचार करता है, आम तौर पर उसे रोक नहीं लगानी चाहिए

कार्यवाहियाँ, गंभीर और असाधारण प्रकृति के मामले को छोड़कर।हालाँकि, उच्च न्यायालय में ऐसी कार्यवाही का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।[379 जी, एच]

10.1 .तत्काल मामले में (महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर रिट याचिका), 1988 तक यह याचिकाकर्ता ही था जो समय-समय पर कई आपत्तियां उठा रहा था और मुकदमे पर रोक लगा रहा था।हो सकता है कि कुछ असामान्य घटनाओं के लिए वही प्रणाली आंशिक रूप से जिम्मेदार थी।प्रतिवादी-शिकायतकर्ता को निश्चित रूप से दोषी नहीं ठहराया जाना था।[383 - डी] सी

10.2 .तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। उचित दिशा

दैनिक आधार पर त्वरित सुनवाई का निर्देश देना है।तदनुसार, इस मामले के लिए नामित विशेष न्यायाधीश को इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेने और इसे समाप्त होने तक दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।डी.

[384 - बी]

आर. एस. नायक बनामए. आर. अंतुले [1984] 2 एस. सी. आर. 495; आर. एस. नायक बनामए. आर. अंतुले [1984] 2 एस. सी. आर. 914; आर. एस. नायक बनामए. आर. अंतुले [1986] 2 एस. सी. सी. 716;

ई.

ए. आर. अंतुले बनामआर. एस. नायक [1988] 2 एस. सी. सी. 602, संदर्भित।11.1 .दूसरी रिट याचिका में, अभिलेख की सामग्री से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष को किसी भी देरी की रणनीति या उस मामले के लिए, आपराधिक कार्यवाही दिल्ली स्थानांतरित होने की तारीख से मुकदमे के संचालन में कोई देरी करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इस अवधि के लिए अदालत की कार्यवाही एफ, यानी 1979 के बाद, स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि इस अवधि के दौरान अभियोजन पक्ष हमेशा मुकदमे को जारी रखने के लिए उत्सुक रहा है।[384 - D] 11.2।दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता के कारावास की शुद्धता या अन्यथा पर या इस सवाल पर कि क्या अभियुक्त को अपनी गिरफ्तारी के 90 दिनों के बाद धारा 167 Cr.P.C के तहत रिहा होने का अधिकार था और इस रिट याचिका में इसी तरह के अन्य प्रश्नों पर निर्णय देना उचित नहीं है।यदि वास्तव में, ऐसी कोई अवैधता की गई है, तो जब भी मामला अंतिम निपटारे के लिए आएगा, अदालत द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।इस संदर्भ में, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता ने एच पर लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए नहीं कहा था

जी.

क.

उचित समय पर उक्त अवैधताओं का लेखा-जोखा।इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष ने पांच साल की अवधि में फैले 151 गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपना मामला पूरा कर लिया है।[385 - सी, डी]

11.3 .इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करना कठिन है कि क्या बी. सी. बी. आई. न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य था, कुछ

बचाव पक्ष के पक्ष में उसके द्वारा दर्ज साक्ष्य, इस कारण से कि यह लंबित आपराधिक संशोधन में सीधे मुद्दे में है।यह कहना पर्याप्त है कि यह पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक वैध आधार प्रदान नहीं करता है

मामले की परिस्थितियाँ।[385- एफ, जी]।

एस.

11.4 .मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करने पर, रद्द करें

इस स्तर पर आरोप और/या आपराधिक कार्यवाही करना उचित और उचित नहीं होगा।इस मामले में उचित आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय से 1986 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 191 का जल्द से जल्द, अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर निपटारा करने का अनुरोध करना है।आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षण याचिका के निपटारे के बाद, विचारण न्यायाधीश मामले को उठाएगा और परिस्थितियों में और अधिमानतः दिन-प्रतिदिन के आधार पर यथासंभव अधिक से अधिक अभियान के साथ आगे बढ़ेगा।[386 - सी, डी]12. इस आशय के निर्देश के लिए आवेदन कि बंबई उच्च न्यायालय में 1982 के विशेष मामले संख्या 24 में अब तक दर्ज किए गए साक्ष्य को विशेष न्यायालय में दर्ज किए गए साक्ष्य के रूप में माना जाएगा जो अब

ई.

उक्त आपराधिक मामले का परीक्षण करें, खारिज कर दिया जाता है।इस स्तर पर ऐसा निर्देश देना न केवल इस न्यायालय के दिनांकित 29.4.1988 के आदेश की समीक्षा के बराबर होगा, बल्कि उक्त आदेश की भावना के विपरीत भी होगा।[340 - ई; 383-बी] ए. आर. अंतुले बनाम।आर. एस. नायक [1988] 2 एस. सी. सी. 602, संदर्भित।

च

मौलिक न्यायनिर्णयःलिखित याचिका (सी. आर. एल) नं.833/90 & 268/87 .

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।

सहित

जी.

1987 की आपराधिक अपील सं. 126 और सी. आर. एल.एम. पी. सं.8605 & 8623/91 .जी. रामास्वामी, राजिंदर सच्चर, के. के. सिन्हा, पी. पी. राव, डॉ. एन. एम.

घटते, जी. बी. भास्मे, आर. के. गर्ग, यू. आर. ललित और ए. के. एससीएन, ए. एन. सदसियार, एच. एस. के. बिसराई, आर. एल. पंजवानी, आर. एस. शर्मा, रंजन द्विवेदी, आर. डी. ओवलाकर,

(ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

335

राजेंद्र बंसी, डी. एन. बेवदी, नितिन प्रधान, प्रवीण पी. राव, सुश्री हेमंतिका ए. वाही, एम. एन. श्रॉफ, प्रमोद सरूप, ए. के. श्रीवास्तव, सुश्री ए. सुभाषिनी, एम. गंगदावा, एस. वी. देशपांडे, बी. बी. सिंह, ए. एस. भास्मे, राजीव धवन, सुश्री रानी जेठमलानी, टी. वी. एस. नरसिम्हाचारी, एस. के. नंदी, प्रवीर चौधरी, अनीप सचथे, सुश्री कुसुम चौधरी, नरेश के. शर्मा, अशोक माथुर, एम. वीरप्पा, के. आर. नाम्बियार, एस. के. अग्निहोत

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस.

बी. पी. जे. ई. वी. ए. रेड्डी, जे. इस अदालत को 12 साल से अधिक समय हो गया है।

हुसैन आरा खातून [1979] (3) एस. सी. आर. 169 में घोषित किया गया है कि त्वरित मुकदमे का अधिकार अनुच्छेद 21 के व्यापक विस्तार और सामग्री में निहित है।इसके बाद कई फैसलों ने इस सिद्धांत की पुष्टि की।कभी भी असहमति का नोट नहीं आया है।यह माना जाता है कि इस अधिकार के उल्लंघन में आरोपों और/या दोषसिद्धि को रद्द करना शामिल है।हालाँकि, अब हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 से नहीं आता है।यह तर्क दिया जाता है कि किसी भी मामले में, यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का केवल एक पहलू है और इससे अधिक कुछ नहीं।यह भी है

डी.

तर्क दिया कि इस अधिकार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप आरोपों और/या दोषसिद्धि को रद्द नहीं किया जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकार, यदि एक भी है, तो एक अनाकार अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत अन्य मौलिक अधिकारों से कुछ कम है।दूसरी ओर, अधिकार के समर्थक चाहते हैं कि हम एक कदम आगे बढ़ें और एक समय सीमा निर्धारित करें जिसके बाद किसी भी आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।वे कहते हैं कि इस तरह की सीमा के बिना, अधिकार केवल एक भ्रम और एक मनगढ़ंत बात बनी रहती है।कई दृष्टिकोण बिंदुओं के समर्थकों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी हैं।हमें दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा संबोधित विस्तृत तर्कों का लाभ मिला।बड़ी संख्या में मामले उद्धृत किए गए हैं।विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं।हम करेंगे।

ई.

च

उचित स्तर पर उन्हें संदर्भित करें।सबसे पहले, इन मामलों को संविधान पीठ के समक्ष कैसे रखा गया है।

2. रिट याचिका संख्या 268/87 और कुछ अन्य आपराधिक अपीलें सामने आईं।

डिवीजन बेंच के समक्ष जब अभियुक्त से यह आग्रह किया गया कि सभी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए एक समय सीमा जी निर्धारित की जाए।इस तरह की समय सीमा के बिना, यह तर्क दिया गया था कि त्वरित मुकदमे के अधिकार की गारंटी केवल एक ढकोसला ही रहेगी।डिवीजन बेंच की राय थी कि उक्त तर्क "एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है" जो "कई मामलों में अधिक बार उत्पन्न होने की संभावना है और इस प्रश्न पर निर्णय के सभी एच 336 में अदालतों में लंबित हजारों आपराधिक मामलों में दूरगामी निष्कर्ष होंगे।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक देश "।तदनुसार, पीठ ने मामलों को संविधान पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।इसके बाद, अन्य मामले भी जोड़े गए। हालाँकि कई मामले हमारे सामने रखे गए हैं, हमने वकील को संकेत दिया कि हम सभी मामलों में तथ्यात्मक पहलुओं में प्रवेश या जांच नहीं करेंगे, बल्कि केवल पहले दो मामलों के तथ्यों को लेंगे।हमने संकेत दिया कि हम इन दो मामलों का निपटारा करेंगे, अर्थात्, 1987 का डब्ल्यू. पी. संख्या 268 (रंजन द्विवेदी बनाम। राज्य) और लाड का डब्ल्यू. पी. संख्या 833

.बी 1990 (ए. आर. अंतुले बनाम।राज्य) और उपयुक्त सिद्धांतों को निर्धारित करने के बाद अन्य मामलों को एक खंड पीठ के पास भेज दें।हम पक्षों की संबंधित दलीलों का विज्ञापन करने से पहले इन दोनों मामलों के तथ्यों पर ध्यान देंगे।3. डब्ल्यू. पी. में तथ्य। नहीं।833/90

एस.

199 सी के डब्ल्यू. पी. संख्या 833 में याचिकाकर्ता ए. आर. अंतुले प्रमुख थे।

1980 से जनवरी 1982 तक महाराष्ट्र के मंत्री रहे।शिकायतकर्ता आर. एस. नायक ने 1 सितंबर, 1981 को अपने आवेदन द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (इसके बाद '1947 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 6 के अनुसार अभियुक्त याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया।अपने आवेदन पर राज्यपाल के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने 11 सितंबर, 1981 को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बॉम्बे के न्यायालय में (आपराधिक मामला संख्या 76 (विविध)/81) के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की।

1 आई>

अभियुक्त और कुछ अन्य।उनका मामला यह था कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त धारा 21 आई. पी. सी. के अर्थ में एक लोक सेवक था और उसने ऐसा किया है।

धारा 161,165 आई. पी. सी. और ई. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 के तहत दंडनीय कई अपराध और धारा 109 और 120-बी. आई. पी. सी. के साथ पठित धारा 383 और 420 आई. पी. सी. के तहत भी विद्वत मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता से उसे संतुष्ट करने का आह्वान किया कि 1947 की धारा 6 द्वारा आवश्यक वैध मंजूरी के बिना शिकायत कैसे

बनाए रखी जा सकती है।एक्ट करें।पक्षकारों को सुनने के बाद, उन्होंने कहा कि इस तरह की मंजूरी के अभाव में, शिकायत धारा 384 और 109 के साथ पठित धारा 420 के तहत अपराधों के संदर्भ को छोड़कर बनाए रखने योग्य नहीं थी

च

और 120-बी आई. पी. सी. इस आदेश पर शिकायतकर्ता द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में 1981 के विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 1742 के माध्यम से सवाल उठाया गया था।

1

4. इस बीच एक श्री पी. बी. सामंत ने इसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर की

याचिकाकर्ता-आर. एस. नायक द्वारा दायर शिकायत में आरोप लगाए गए कई जी सहित शक्ति के दुरुपयोग के कई कृत्यों का आरोप लगाने वाला आरोपी।रिट याचिका की अनुमति दी गई थी।12 जनवरी, 1982 को जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

5. विशेष आपराधिक आवेदन सं:1742 शिकायत द्वारा दायर 1981 का

चींटी को उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल, 1982 को खारिज कर दिया था।आदेश के खिलाफ, महाराष्ट्र के राज्य एच ने विशेष अनुमति के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया, जिसे ए. आर. एंटूले बनाम पर अस्वीकार कर दिया गया था।

337

आर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

28 जुलाई, 1982।हालाँकि, उसी दिन, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 1947 के अधिनियम की धारा 6 के तहत उसमें निर्धारित अपराधों के संबंध में मंजूरी दे दी।इस आधार पर शिकायतकर्ता/प्रतिवादी ने विशेष न्यायाधीश, बॉम्बे के न्यायालय में एक नई शिकायत दायर की (आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई, जिसे इसके बाद '1952 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया) जिसे आरोपी और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 1982 का आपराधिक मामला संख्या 24 के रूप में दर्ज किया गया था।इस शिकायत में मुख्य आरोप यह था कि आरोपी ने कुछ न्यासों के नाम पर जनता से धन प्राप्त करने के लिए बी योजना शुरू की थी और वह ऐसे डब्ल्यू. ए. एन. ए. न्यासों के लिए धन एकत्र करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था।उनकी सभी गतिविधियों को मुख्यमंत्री के रूप में उनके आधिकारिक पद के घोर दुरुपयोग के रूप में वर्णित किया गया था। आरोपों के समर्थन में कई उदाहरण भी दिए गए।विशेष न्यायाधीश (श्री पी. एस. भुट्टा) ने इसका संज्ञान लिया और अभियुक्त को जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया।जारी की गई प्रक्रिया के जवाब में, अभियुक्त उपस्थित हुआ और उसने विशेष न्यायाधीश की अधिकारिता पर दो आपत्तियाँ उठाईं।:

(i) विशेष न्यायाधीश को 1952 के अधिनियम की धारा 6 (1) (ए) और (बी) में उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है (जिसमें धारा 161 और 165 आई. पी. सी. और डी. के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं)।

1947 अधिनियम की धारा 5) एक निजी शिकायत के आधार पर; और (ii) जहां किसी क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं, राज्य सरकार द्वारा 1952 के अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत स्थानीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना के अभाव में, श्री भुट्टा को 1982 के आपराधिक मामले संख्या 24 पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। (धारा 7 (2) में प्रावधान है कि "धारा 6 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का मुकदमा विशेष न्यायाधीश द्वारा उसके भीतर के क्षेत्र के लिए किया जाएगा।

जिसे वह प्रतिबद्ध किया गया था, या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायाधीश हैं, उनमें से एक द्वारा जो निर्दिष्ट किया जाए

!

राज्य सरकार द्वारा इस ओर से।”)

च

6. विशेष न्यायाधीश श्री पी. एस. भुट्टा ने दोनों आपत्तियों पर फैसला सुनाया।

जिसके बाद अभियुक्त ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

1982 का आपराधिक संशोधन आवेदन सं. 510।उक्त संशोधन को लंबित रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने 1952 के अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश श्री एस. बी. सुले को उक्त विशेष आपराधिक मामला सं.1982 का आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 510 बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष निपटारे के लिए आया जिसने 7 मार्च, 1983 को इसे खारिज कर दिया।डिवीजन बेंच के दो विद्वान न्यायाधीशों ने दो अलग-अलग लेकिन सहमत राय दी

आयन।आरोप की पहली आपत्ति के संबंध में।) उन्होंने अभिनिर्धारित किया कि 1947 अधिनियम एच की धारा 5-ए के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

जी 338

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए विशेष न्यायाधीश के लिए पूर्व शर्त नहीं थी।1952 के अधिनियम की धारा 8 के तहत एक अपराध का संज्ञान लेते हुए और इसलिए, विशेष न्यायाधीश था

किसी निजी शिकायत पर भी धारा 6 (1) में उल्लिखित अपराध का संज्ञान लेने के लिए बाध्य।दूसरी आपत्ति के संबंध में, उन्होंने इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि आवश्यक अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी थी।

7 :श्री आर. बी. सुले ने इस मामले को उठाया और इसे आगे बढ़ाने की मांग की।उस समय, याचिकाकर्ता अभियुक्त ने 8 जुलाई, 1983 को अपने समक्ष दो आवेदन दायर किए, एक इस आधार पर कि उसके खिलाफ आरोप निराधार है और आगे इस आधार पर कि चूंकि वह एम. एल. ए. था, इसलिए राज्यपाल की मंजूरी के बिना अपराधों का संज्ञान वैध नहीं था और दूसरा सी मामले की सुनवाई को स्थगित करने के लिए था।विद्वान विशेष न्यायाधीश (श्री आर. बी. सुले) ने अभियुक्त के पहले तर्क को बरकरार रखा और कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना मामला नहीं चल सकता है।तदनुसार, उन्होंने आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने एक विशेष अनुमति याचिका के साथ-साथ एक रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।उन्होंने श्री डी. आर. बी. सुले के उसी आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक संशोधन भी दायर किया, जिसे संशोधन आवेदन को बाद में इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।इन मामलों की सुनवाई डी. ए. देसाई, जे. की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ द्वारा की गई और 16 फरवरी, 1984 (1984 (2) एस. सी. आर. 495 में रिपोर्ट) को निपटाया गया।इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति आवेदन पर

}

उपरोक्त, इस न्यायालय ने विशेष अनुमति प्रदान की थी, जो इस रूप में पंजीकृत थी

ई.

1983 की आपराधिक अपील सं. 247।इस अपील की सुनवाई भी उसी संविधान पीठ द्वारा की गई थी और उसी दिन यानी 16 फरवरी, 1984 को इसका निपटारा कर दिया गया था (निर्णय 1984 (2) एस. सी. आर. के पृष्ठ 914 पर सूचित किया गया है)।पहले उल्लिखित निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एम. एल. ए. धारा 21 आई. पी. सी. के अर्थ में 'लोक सेवक' नहीं है और इसलिए मंजूरी का प्रश्न नहीं उठता है।एफ तदनुसार, इसने श्री आर. बी. सुले के अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के आदेश को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि मुकदमा उस चरण से आगे बढ़ना चाहिए जिस पर अभियुक्त को आरोपमुक्त किया गया था।ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्देश दिएः

" अभियुक्त एक प्रमुख राज्य-महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री था।सितंबर को शुरू किए गए अभियोजन द्वारा

जी.

में 11,1981, उनके चरित्र और अखंडता एक बादल के नीचे आया था.लगभग ढाई साल बीत चुके हैं और मामला एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है।एक त्वरित परीक्षण मुख्य रूप से हित में है

अभियुक्त और अनुच्छेद 21 का अधिदेश।आपराधिक मामले का शीघ्र निपटान अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों के हित में है। इसलिए, 1982 का विशेष मामला संख्या 24 और विशेष मामला

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे. जे.

339

नं. ग्रेटर बॉम्बे के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित ए श्री आर. बी. सुले को वापस ले लिया जाता है और बॉम्बे के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसमें विद्वान मुख्य न्यायाधीश से इन दोनों मामलों को उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को सौंपने का अनुरोध किया जाता है।ऐसा होने पर

नियुक्त किए जाने पर, विद्वान न्यायाधीश दिन-प्रतिदिन मुकदमा आयोजित करके मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

8. 1983 की आपराधिक अपील संख्या 247 (1984 (2) एस. सी. आर. 914) में अपने निर्णय में, यह न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ से सहमत था कि 1947 अधिनियम की धारा 5-ए के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच 1952 अधिनियम की धारा 8 के तहत संज्ञान लेने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती नहीं है और यह कि एक निजी शिकायत पर भी एक विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है।इस प्रकार, इस अदालत ने अभियुक्त द्वारा सी विशेष न्यायाधीश के समक्ष उठाई गई दो आपत्तियों में से पहली को खारिज कर दिया-और उनके साथ-साथ सी विशेष न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा भी खारिज कर दिया गया।

बॉम्बे उच्च न्यायालय।जहाँ तक अभियुक्त द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति है।संबंधित, इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था।इसने केवल उस ओर से बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया।हमें दोहराना चाहिए कि संविधान पीठ का पूरा निर्णय डी

केवल पहली आपत्ति से संबंधित है न कि दूसरी से।रिपोर्ट के पृष्ठ 921 पर, अदालत ने केवल दूसरी आपत्ति के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ की टिप्पणियों पर ध्यान दिया और इसे वहीं छोड़ दिया।19. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में (1984 (2) एस. सी. आर. 495 557 पर) 1982 का विशेष आपराधिक मामला संख्या 24 श्री न्यायमूर्ति ई.

बॉम्बे उच्च न्यायालय के एस. एन. खत्री।विद्वान न्यायाधीश के समक्ष, अभियुक्त ने आपत्ति जताई कि उक्त विशेष मामले की सुनवाई केवल 1952 के अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास इसका परीक्षण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।यह और अभियुक्त द्वारा उठाई गई कुछ अन्य आपत्तियों को विद्वान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वह इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देश से बंधे थे।खत्री, जे. के आदेश पर एफ द्वारा सवाल उठाया गया था।

1

इस अदालत में अभियुक्त लेकिन 17 अप्रैल, 1984 को खारिज कर दिया गया (1984 (3) एस. सी. आर. 482 में सूचित)। बाद में कार्यवाही डी. एन. मेहता, जे. को स्थानांतरित कर दी गई, जिन्होंने 21 आरोप बनाए लेकिन 22 अन्य शीर्षों के तहत आरोप तय करने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तावित।शिकायतकर्ता उक्त आदेश के खिलाफ इस अदालत में आया था क्योंकि उसने कुछ आरोप तय करने से इनकार कर दिया था, जिन मामलों का अंततः 1986 में निपटारा (अनुमति) कर दिया गया था (1986 (2) एस. सी. सी. 716 में सूचित)।द जी.

इसके बाद कार्यवाही को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. एस. शाह को स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने 79 आरोप तैयार किए और मुकदमे के साथ आगे बढ़े।कई महीनों में कई गवाहों से पूछताछ की गई।जबकि, अभियुक्त ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत फिर से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। (सीआरएल।) सं. 542/86) धारा 197 करोड़ की संवैधानिक

वैधता पर सवाल उठाते हुए।उनके द्वारा 1986 का पी. सी. एस. एल. पी. सं. 2519 भी एच. के आदेशों के विरुद्ध दायर किया गया था।

$ ए.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

340

ए. शाह, जे. ने 79 आरोप बनाए।एक और एस. एल. पी. (सीआरएल।) नं. 2518/86 उनके द्वारा शाह, जे. के एक अन्य आदेश के खिलाफ दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा बनाए गए आरोपों के लिए धारा 197 करोड़ के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।उपरोक्त मामलों में पी. सी. को विशेष अनुमति दी गई और उच्च न्यायालय में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।अनुच्छेद 32 के तहत याचिका और उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं से उत्पन्न अपीलों को इस बी अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भेजा गया और उन पर विचार किया गया।हालांकि, सात न्यायाधीशों की पीठ ने डब्ल्यू. पी. नंबर 542/86 और एस. एल. पी. नंबर 2518/86 को दूसरे एस. एल. पी. से अलग कर दिया। इसने उन दोनों मामलों की अलग से सुनवाई करने का निर्देश दिया।इसने केवल एस. एल. पी. सं. 2519/86 से उत्पन्न अपील पर सुनवाई की।29 अप्रैल, 1988 को दिए गए अपने फैसले से पीठ ने अपील (विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) से उत्पन्न) को मंजूरी दे दी। 1986 का सं. 2519) और 16 फरवरी, 1984 (1984 (2) एस. सी. आर. 495) के अपने फैसले में निहित इस सी अदालत के निर्देशों के बाद लिए गए उक्त विशेष मामले में सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।इसने मुकदमे को कानून के अनुसार, यानी 1952 के अधिनियम के तहत आगे बढ़ने का निर्देश दिया।इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि इस न्यायालय के 16 फरवरी, 1984 के निर्देश के अनुसरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय में की गई सभी कार्यवाहियां-शिकायतकर्ता ने व्यावहारिक रूप से एक वर्ष की अवधि में दर्ज अपने साक्ष्य को पूरा कर लिया था-अमान्य हो गईं और मामले को 1952 के अधिनियम के अनुसार विशेष न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ाना पड़ा (ऊपर बताए गए तथ्य इस अदालत के निर्णयों से लिए गए हैं)।

10. अभिलेख में यह नहीं बताया गया है कि 29 अप्रैल, 1988 के बाद क्या हुआ।यह स्पष्ट नहीं है कि बंबई उच्च न्यायालय ने मामले का अभिलेख विशेष न्यायाधीश को भेजा था या नहीं और यदि भेजा था तो किस विशेष न्यायाधीश को।बनो।

ई.

ताकि तथ्य यह रहे कि मामले में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि यह मामला 1952 के अधिनियम के तहत नियुक्त किसी भी विशेष न्यायाधीश द्वारा लिया गया था। <आई. डी. 1 पर, प्रतिवादी शिकायतकर्ता ने इस अदालत के समक्ष एक आवेदन (1990 का सी. एम. पी. संख्या 1946) दायर किया ताकि बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्राप्त और दर्ज किए गए साक्ष्य को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायालय में साक्ष्य के रूप में माना जा सके।

विशेष न्यायाधीश।1991 तक इस आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, जब यह

च

इस मामले को हमारे सामने रखा गया था।इस बीच, बॉम्बे के एक वकील, श्री मोरे ने मार्च, 1990 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे रिट याचिका (सी. आर. एल.) कहा जा रहा था। महाराष्ट्र सरकार को 1982 का उक्त विशेष मामला संख्या 24 का विचारण करने के लिए एक विशेष न्यायाधीश नामित करने के निर्देश के लिए 1990 का सं. 281।इस रिट याचिका के लिए, याचिकाकर्ता-अभियुक्त को प्रथम जी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, जबकि आर. एस. नायक (शिकायतकर्ता) और महाराष्ट्र राज्य को क्रमशः प्रतिवादी 2 और 4 के रूप में शामिल किया गया था।रिट याचिका 23.4.1990 पर एक खंड पीठ के समक्ष आई और एक निर्देश के साथ इसका निपटारा किया गया।आदेश के प्रासंगिक भाग को निकालना उचित होगा ताकि उन परिस्थितियों को सामने लाया जा सके जिनमें वह निर्देश दिया गया थाः

" उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय के अनुसरण में, यह

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

341

राज्य सरकार के लिए अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायाधीश ए की नियुक्ति को अधिसूचित करना आवश्यक है।

आपराधिक संशोधन अधिनियम, 1952 के अनुसार।हालांकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय 29 अप्रैल, 1988 को दिया गया था और लगभग दो साल बीत चुके थे, लेकिन राज्य सरकार ने विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की है।

याचिकाकर्ता एक अधिवक्ता है और उसने 7 मार्च, 1990 को यह याचिका दायर की है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका 12 मार्च, 1990 को हमारे समक्ष रखी गई थी और हमने निर्देश दिया था।प्रतिवादी संख्या 2 को यह स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा कि क्या सी शिकायतकर्ता विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहता है।राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया था।16 अप्रैल, 1990 को शिकायतकर्ता हमारे सामने पेश हुआ और सूचित किया कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन जारी रखने का इच्छुक है।बयान को ध्यान में रखते हुए, हमने याचिका स्वीकार कर ली।शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3-महाराष्ट्र राज्य ने नियम की सेवाओं को माफ कर दिया।मूल अभियुक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 पर नियम 1 लागू नहीं किया जा सका।5. आज जब मामला उठाया गया तो राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने बयान दिया कि इस याचिका की सुनवाई को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य सरकार मुकदमे के संचालन के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कर रही है और आवश्यक अधिसूचना आज से दो महीने की अवधि के भीतर प्रकाशित की जाएगी।विद्वान महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति ए. आई. आर. 1988 सर्वोच्च न्यायालय 1531 में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप की गई है।चूंकि नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में की जानी है और जैसा कि महाधिवक्ता एक एफ के भीतर ऐसी नियुक्ति करने का वादा करता है

अभियुक्त पर सेवा के अभाव में इस याचिका की सुनवाई को दो महीने की अवधि के लिए स्थगित करना आवश्यक नहीं है। महाधिवक्ता का बयान जी याचिका का निपटारा करने के लिए पर्याप्त है और यह बयान किसी भी तरह से अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा।6. तदनुसार, विद्वान महाधिवक्ता के बयान को देखते हुए, याचिका में मांगी गई राहत अब नहीं बची है और पहले जारी किए गए नियम को हटा दिया गया है।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच 342

उपरोक्त निर्देश के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया

क.

मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश को नामित करने वाली अधिसूचना 19.6.1990।11. इस बीच, याचिकाकर्ता ने त्वरित सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर 1982 के आपराधिक मामले संख्या 24 को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका दायर की।

16.9.1991 पर, विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों को आगे के कदमों के लिए उसके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किए।7.10.1991 पर, याचिकाकर्ता आरोपी को जमानती वारंट जारी किए गए और 11.10.1991 पर, उसे जमानत दे दी गई।

डब्ल्यू. पी. में तथ्य। नहीं।268/87 :

एस.

तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री श्री एल. एन. मिश्रा की 2 जनवरी, 1975 को रेलवे स्टेशन, समस्तीपुर में एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई थी।बिहार राज्य पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी।10 जनवरी, 1975 को सी. बी. आई. ने जाँच अपने हाथ में ले ली, लेकिन बिहार सी. आई. डी. डी. जाँच से जुड़ा रहा।फरवरी, 1975 के पहले सप्ताह में दो व्यक्तियों, अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था।अरुण कुमार ठाकुर का बयान

दंड संहिता की धारा 164 के तहत राष्ट्रीय बयान दर्ज किया गया था।पी. सी. 21.2.1975 पर।लेकिन मई-जून, 1975 में या उसके आसपास सी. बी. आई. द्वारा की गई जाँच ने एक नया मोड़ ले लिया।ऊपर उल्लिखित दो अरुण कुमारों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी थी।अब आनंद मार्ग और उसके सदस्य जाँच का विषय बन गए।ई 2.7.1977 पर, आनंद मार्ग को सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता, रंजन द्विवेदी को 6.7.1975 पर गिरफ्तार किया गया था।24.7.1975 पर, एक विक्रम को गिरफ्तार किया गया जो सरकारी गवाह बन गया।दंड संहिता की धारा 164 के तहत उनका इकबालिया बयान।पी. सी. को 14.8.1975 पर दर्ज किया गया था।आई. डी. 1 पर सी. बी. आई. ने अदालत से अनुरोध किया कि मूल रूप से गिरफ्तार किए गए आरोपी अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर को आरोपमुक्त कर दिया जाए क्योंकि आगे की जांच से यह साबित हो गया है कि उन्होंने ऐसा किया है।एफ का अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।इसके अनुसार, अपराध वास्तव में आनंद मार्ग के सदस्यों द्वारा किया गया था।आई. डी. 1 पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।

1

13. याचिकाकर्ता को 6.7.1975 पर गिरफ्तार किया गया था जैसा कि ऊपर बताया गया है।कहा जाता है कि वह जी इंडिया के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री ए. एन. रे की हत्या के प्रयास के अपराध में शामिल था।वह मुकदमा पहले दिल्ली में चलाया गया और 1.12.1976 पर समाप्त हुआ।याचिकाकर्ता को दोषी पाया गया और कुछ अन्य लोगों के साथ चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की और जमानत प्राप्त की, लेकिन उसे रिहा नहीं किया जा सका, क्योंकि वह एल. एन. मिश्रा हत्या मामले में भी शामिल था।उन्हें पटना जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और 19.12.1976 पर पटना अदालत के समक्ष पेश किया गया।जनवरी, 1977 के पहले सप्ताह में,

एच.

:

} ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक (रेड्डी, जे.)

343

याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्तों ने कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया जो तब तक उन्हें प्रदान नहीं किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि वे उन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिन्हें विद्वान मजिस्ट्रेट ने बरकरार रखा था।याचिकाकर्ता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया।विद्वान कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष कई अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए और इस स्तर पर आदेश पारित किए गए।उनमें से कुछ अभियुक्तों के लिए वकील बी की नियुक्ति, जेल में उनके साथ व्यवहार, जेल में उनके लिए पैदा की गई कठिनाइयों आदि से संबंधित थे।

14. 30 मार्च, 1978 को याचिकाकर्ता को इस अदालत ने जमानत दे दी और कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया।

एस.

इस स्तर पर, ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रम, जो सरकारी गवाह बन गया था और एक इकबालिया बयान दिया था, पटना जेल में रहते हुए अपना इकबालिया बयान वापस ले लिया।जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना इकबालिया बयान वापस लिया, उनके संबंध में काफी विवाद है।, चाहे वह स्वेच्छा से किया गया हो या दबाव में।बिहार सरकार के अधिकारी।जो भी हो, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां सी. बी. आई. और बिहार सी. आई. डी. एक दूसरे के खिलाफ झूठे डी निहितार्थ के आरोपों का स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे थे।ऐसा प्रतीत होता है कि सी. बी. आई. ने महसूस किया है कि वह पटना में अपने मामले पर ठीक से मुकदमा

नहीं चला सकता है।इसलिए, भारत के महान्यायवादी ने मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए इस अदालत का रुख किया। इस अदालत ने आरोपों की सच्चाई या अन्यथा में गए बिना, जिसके आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई थी, स्थानांतरण का आदेश दिया।इस तरह के स्थानांतरण के बाद, दिल्ली के विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 25.5.1980 पर मामले को सत्रों को सौंप दिया।ई मामला श्री डी. सी. अग्रवाल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली को सौंप दिया गया था।अभियुक्त को मार्च, 1980 में उसके सामने पेश किया गया था।जनवरी, 1981 में आरोप तय किए गए और मुकदमा शुरू हुआ।

15. सुनवाई की पहली कुछ तिथियों को जमानत के लिए आवेदन और बनाए गए आरोपों की वैधता सहित विविध आवेदनों द्वारा लिया गया था।एक या दूसरे अभियुक्त की अनुपलब्धता के कारण मामले को कुछ तारीखों पर स्थगित करना पड़ा।पीडब्लू-1 की परीक्षा फरवरी, 1981 में शुरू हुई थी।पीडब्लू-1 (एम. एम. श्रीवास्तव)-अनुमोदनकर्ता के साक्ष्य को दर्ज करने में कई दिन लगे। दूसरे सरकारी गवाह विक्रम की गवाही अप्रैल, 1981 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई।उसके साक्ष्य में भी कई दिन लगे।हमें फरवरी, 1981 से लेकर आई. डी. 1 तक मामले की प्रगति के बारे में पता चला है, जिस तारीख तक अभियोजन पक्ष ने जांच अधिकारी और अन्य गवाहों सहित 151 गवाहों से पूछताछ की।

च

अनुमोदनकर्ता।हमारे सामने रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने पांच वर्षों की इस अवधि के दौरान कभी भी देरी करने की रणनीति नहीं अपनाई और न ही वह कभी लापरवाही या लापरवाही का दोषी था।साक्ष्य की बहुत मात्रा और कई हस्तक्षेपकारी अंतर्वर्ती कार्यवाही के कारण, मुकदमे ने इस एच को लिया

जी 344

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक लंबा।हालाँकि, 16.4.1986 पर, अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बंद कर दिया और उसके द्वारा उद्धृत शेष गवाहों को आरोपमुक्त कर दिया।1.5.1986 पर, बचाव पक्ष के वकील ने अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों को बरी करने पर आपत्ति जताई, जिन्हें उसने उद्धृत किया था।अभियुक्तों ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों से पूछताछ करने से पहले उनमें से 13 गवाहों को अदालती गवाह के रूप में बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया।पी. सी. अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए अनुरोध का विरोध किया कि बी अभियुक्तों द्वारा नामित 13 गवाहों को या तो अभियुक्तों द्वारा जीत लिया गया है या अभियोजन मामले को उजागर करने के लिए आवश्यक नहीं हैं।आई. डी. 1 पर, निचली अदालत ने उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।इसे 17.9.1986 पर स्वीकार कर लिया गया और मुकदमे में आगे की सभी कार्यवाही रोक दी गई।पुनरीक्षण याचिका अभी भी लंबित है और रोक जारी है।

एस.

16. इस मामले के संबंध में हमारे ध्यान में लाए गए कुछ और तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है।

वर्ष 1978 के दौरान, बिहार सरकार ने श्री वी. एम.

तारकुंडे, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, मामले के तथ्यों की जांच करने और अपनी डी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए।फरवरी 1979 में, श्री तारकुंडे ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और आनंद मार्ग के अन्य सदस्यों को उक्त मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वास्तव में दोषी व्यक्तियों को उजागर करने के लिए एक नई जांच आवश्यक है।

याचिकाकर्ता के आदेश को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ

ई पुनरीक्षण (दस्तावेजों की आपूर्ति के संबंध में) याचिकाकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने भी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त दस्तावेज, हालांकि समर्पण के चरण में प्रासंगिक नहीं हैं, मुकदमे के चरण में प्रासंगिक हो सकते हैं और अभियुक्त को उनकी आपूर्ति पर मुकदमे के चरण में विचार किया जा सकता है।अभियोजन पक्ष का कहना है कि अभियुक्तों द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज मुकदमे के चरण में उन्हें प्रदान कर दिए गए हैं।

च

नवंबर, 1981 में, श्री डी. सी. अग्रवाल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को बिक्री कर न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गयाःएक, श्री एस. एम. अग्रवाल को उनके स्थान पर तैनात किया गया था।अभियुक्त-याचिकाकर्ता का कहना है कि श्री डी. सी. अग्रवाल के बिक्री कर न्यायाधिकरण जाने के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने अकेले जी के समक्ष इस मामले को आगे बढ़ाने की मांग की और उच्च न्यायालय द्वारा श्री एस. एम. अग्रवाल को उक्त मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायाधीश के रूप में नामित करने वाली अधिसूचना के बावजूद, उत्तराधिकारी न्यायाधीश, श्री एस. एम. अग्रवाल के समक्ष आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि 17 दिसंबर, 1981 को अभियोजन पक्ष के कहने पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त मामले को श्री डी. सी. अग्रवाल (बिक्री कर न्यायाधिकरण) को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी।मामला अंततः इस अदालत तक पहुँचा जिसने ए. आर. एंटूले बनाम. को निर्देश दिया।

आर. एस. नायक (रेड्डी, जे.)

345

कि श्री डी. सी. अग्रवाल से मामला वापस लिया जाए और दिल्ली में एक अन्य सत्र न्यायाधीश को सौंपा जाए।इस बारे में विरोधाभासी संस्करण हैं कि अभियोजन पक्ष श्री डी. सी. अग्रवाल के समक्ष मामले को आगे क्यों बढ़ाना चाहता था।अभियोजन पक्ष का कहना है कि इस अदालत के आदेशों के अनुसार केवल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट एक न्यायाधीश ही इस मामले की सुनवाई कर सकता था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री डी. सी. अग्रवाल को इसकी सुनवाई के लिए नामित किया था; जब तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नामित नहीं किया गया था, अभियोजन पक्ष का कहना है कि मामला केवल श्री डी. सी. बी. अग्रवाल के समक्ष ही चल सकता था, जहां भी वह तैनात थे।दूसरी ओर, अभियुक्त याचिकाकर्ता का मामला यह है कि अभियोजन पक्ष अकेले श्री डी. सी. अग्रवाल के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने पर आमादा था क्योंकि उन्होंने उसे अपने मामले के प्रति अनुकूल झुकाव पाया और बिक्री कर न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष का उक्त आग्रह मामले में उसकी अनुचित रुचि को दर्शाता है।

क.

एस.

17. श्री रंजन द्विवेदी, डब्ल्यू. पी. सं. 268/87 में याचिकाकर्ता, एक अधिवक्ता

इस अदालत में वकालत करते हुए, उन्होंने खुद मामले पर बहस करने की कोशिश की।कुछ समय तक उनकी बात सुनने के बाद, हमने सोचा कि यह उनके हित में है, और तदनुसार, उन्हें उनकी ओर से पेश होने के लिए एक वकील को नियुक्त करने की सलाह दी।तदनुसार, श्री ए. के. सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता उनकी ओर से पेश हुए और मामले पर बहस की।हम उचित स्तर पर उनके डी तर्कों का उल्लेख करेंगे।हालाँकि, बाद की तारीख में, याचिकाकर्ता ने प्रतिनिधित्व किया कि वह नहीं चाहते कि उनके मामले में श्री ए. के. सेन द्वारा आगे बहस की जाए।याचिकाकर्ता को अभी भी विद्वान महान्यायवादी की दलीलों का जवाब देना था।श्री ए. के. सेन ने भी मामले से पीछे हटने की अनुमति मांगी।उन्हें अनुमति दी गई थी।

ई.

मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य को रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए आवेदन किया।हमने आवेदन की अनुमति दी।बिहार राज्य ने अपनी ओर से पेश होने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी को नियुक्त किया।तदनुसार, विद्वान वकील पेश हुए और 19 नवंबर 1991 को मामले में बहस की।उन्होंने यह रुख अपनाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला एफ का हकदार है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर खारिज किया जाना।उन्होंने कई तथ्यों को हमारे ध्यान में लाया।उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर जारी रहना था।

लेकिन सुनवाई की अगली तारीख यानी 22 नवंबर, 1991 को श्री राम जेठमलानी ने अनुरोध किया कि उन्हें मामले से पीछे हटने की अनुमति दी जाए।

चूंकि बिहार सरकार ने तब से उन्हें बहस नहीं करने का निर्देश दिया है

जी.

तथ्यों पर मामला।उन्होंने कहा कि वह इस तरह के किसी भी प्रतिबंध के तहत काम नहीं कर सकते।हमने उन्हें मामले से हटने की अनुमति दी।इस स्तर पर, याचिकाकर्ता ने अभी तक विद्वान अटॉर्नी जनरल को अपना जवाब नहीं दिया था।याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि चूंकि वह अपने मामले का उचित प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए उन्हें श्री राम जेठमलानी की सहायता दी जा सकती है:न्यायमित्र।हमारे अनुरोध पर, श्री जेठमलानी ने न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता करने के लिए सहमति व्यक्त की और एच 1346 जारी रखा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

तथ्यों पर उनके तर्क।उन्होंने हमारे संज्ञान में कई तथ्य लाए जो उनके अनुसार पूरी कार्यवाही को दूषित करते हैं और इस अदालत द्वारा कार्यवाही को रद्द करने का आह्वान करते हैं।हम उचित स्तर पर उनका उल्लेख करेंगे।

18. डब्ल्यू. पी. में निवेदन सं.833/90 .

श्री पी. पी. राव, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील-मामले में आरोपी

डब्ल्यू. पी. नं. 833/90 ने निम्नलिखित तर्कों का आग्रह किया:(i) त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 से आता है, जैसा कि इस न्यायालय के कई फैसलों में कहा गया है;

एस.

((ii) त्वरित सुनवाई के अधिकार को सार्थक, प्रवर्तनीय और प्रभावी बनाने के लिए, एक बाहरी सीमा होनी चाहिए जिसके आगे कार्यवाही जारी रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।इस न्यायालय ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में ऐसी बाहरी सीमा निर्धारित की है; पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा किए गए सामान्य आवेदन के लिए भी इसी तरह का नियम विकसित किया जाना चाहिए।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 एक बाहरी रेखा खींचने के मामले में मार्गदर्शन प्रदान करती है जिसके आगे आपराधिक मुकदमे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।यद्यपि धारा 468 केवल छोटे अपराधों पर लागू होती है, इसके सिद्धांत को बड़े अपराधों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

एक्स

डी.

ई.

(iii) मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सात साल से अधिक की देरी को अनुचित और अनुचित माना जाना चाहिए। जाँच में लगने वाले समय को गिना जाना चाहिए।

इस सात साल की ओर।किसी भी स्थिति में, किसी आपराधिक कार्यवाही को, उसके सभी चरणों के साथ, अपराध के पंजीकरण की तारीख से दस साल से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।बाहरी सीमा के अभाव में,

च

त्वरित सुनवाई का अधिकार एक भ्रम बन जाता है।

(iv) यहां तक कि अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत में अदालतें यह अभिनिर्धारित करती रही हैं कि किसी मुकदमे को एक निश्चित अवधि से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।कई मामलों में, इस अदालत ने मुकदमे को फिर से चलाने या जारी रखने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है, जहां कार्यवाही लंबे समय से लंबित है।

जी.

यहां तक कि जहां यह संतुष्ट था कि बरी करने का आदेश कानूनी रूप से सक्षम नहीं था।पुनः मुकदमा अधिक शीघ्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।मुकदमे के मामले में जो देरी नहीं हो सकती है, वह अभी भी खराब होगी।

एक पुनः परीक्षण।

(v) इस मामले में, हालांकि लगभग दस साल की अवधि बीत चुकी है,

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

347

कानून के अनुसार मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है।विशेष रूप से, 1988 में इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय ए के बाद, शिकायतकर्ता इस मामले पर सो रहा है।उन्होंने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।तीन साल की अवधि के बाद और जब इस रिट याचिका को सुनवाई के लिए रखा गया, तो शिकायतकर्ता जाग गया और कार्यवाही फिर से शुरू की।अभियुक्त-याचिकाकर्ता हो रहा है।इस मामले में परेशान किया गया।

(vi) प्रतिवादी-शिकायतकर्ता राजनीतिक शत्रुता के कारण याचिकाकर्ता का पीछा कर रहा है।वह बी. जे. पी. के हैं, जबकि याचिकाकर्ता कांग्रेस (आई) के हैं।चूंकि प्रतिवादी का पक्ष राजनीतिक रूप से याचिकाकर्ता का सामना करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह अदालती कार्यवाही के माध्यम से उसका पीछा कर रहा है और उसे काट रहा है।हाल के आम चुनावों में याचिकाकर्ता को संसद के लिए चुना गया है।उनका राजनीतिक करियर और भविष्य की संभावनाएं इस मुकदमे से प्रभावित हो रही हैं जो राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है।

Â

(vii) मामले की सभी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द कर दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए।

19. श्री घटाटे, शिकायतकर्ता (आर. एस. नायक) के विद्वान वकील, इस प्रस्ताव पर विवाद नहीं करते हुए कि त्वरित मुकदमे का अधिकार कला में निहित है।21 संविधान ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में अभियुक्त का आचरण ई

उसे किसी भी राहत से वंचित कर देता है।उनके अनुसार, अप्रैल, 1988 में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के अनुसार उपयुक्त विशेष न्यायाधीश को रिकॉर्ड भेजना बॉम्बे उच्च न्यायालय का कर्तव्य था।उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। शिकायतकर्ता को विशेष अदालत से कोई नोटिस भी नहीं मिला था।आम तौर पर, उन्होंने बताया, जब किसी मामले को उच्च न्यायालय से निचली अदालत में भेजा जाता है, तो बाद वाला पक्षकारों को एफ.

उससे पहले एक निर्दिष्ट तिथि पर।हालांकि, इस मामले में ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि श्री सुले के विशेष न्यायाधीश नहीं रहने के कारण, सरकार बॉम्बे के विशेष न्यायाधीशों में से एक को इस मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित करने के लिए बाध्य थी; ऐसा नहीं किया गया था और इसलिए, किसी भी विशेष न्यायाधीश को मामले में शामिल नहीं किया गया था।ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को मुकदमे के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए दोषी नहीं पाया जा सका।उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक श्री जी मोरे ने एक रिट याचिका दायर नहीं की और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक निर्देश नहीं दिया, तब तक सरकार ने उक्त मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना जारी नहीं की।उन्होंने हमारे संज्ञान में यह भी लाया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में शिकायतकर्ता से पूछा था कि क्या वह अभियोजन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया था कि वह मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि विशेष न्यायाधीश एच. 348 के बाद

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए नामित किया गया था, शिकायतकर्ता ने उसे स्थानांतरित कर दिया और अब कार्यवाही शुरू हो गई है।वह इस तथ्य को भी हमारे ध्यान में लाते हैं कि शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में दर्ज साक्ष्य को विशेष न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य के रूप में मानने के लिए 31.5.1989 के रूप में एक आवेदन दायर किया है।उन परिस्थितियों में, उन्होंने कहा, यह नहीं कहा जा सकता है कि

शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष के साथ आगे बढ़ने में अनिच्छुक था या वह मामले पर सो रहा था।उन्होंने अभियुक्त-याचिकाकर्ता के बी आचरण पर जोर दिया कि वे कार्यवाही में देरी करने और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने इस अदालत के निर्णयों के कुछ अंशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिनका यहाँ पहले उल्लेख किया गया है।उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने किसी भी समय मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है और वह मामले को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार और उत्सुक रहे हैं।उन्होंने आपराधिक कार्यवाही के संचालन के लिए एक सामान्य समय सीमा निर्धारित करने के विचार का विरोध किया।शिकायतकर्ता द्वारा रिट याचिका में कोई सी काउंटर-हलफनामा दायर नहीं किया गया है।20. महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील श्री भासमे ने भी ऐसा नहीं किया।इस प्रस्ताव पर विवाद करें कि त्वरित परीक्षण का अधिकार कला से आता है। 21 , यद्यपि उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कोई बाहरी सीमा नहीं होनी चाहिए।उन्होंने प्रस्तुत किया कि मामले की डी कार्यवाही में देरी, यदि कोई हो, के लिए राज्य किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं था।हालाँकि, वकील ने कहा कि इस अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के बाद, शिकायतकर्ता को उचित निर्देशों के लिए या विशेष न्यायाधीश को नामित करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय या सरकार का रुख करना चाहिए था, और यह कि उसकी निष्क्रियता अस्पष्ट बनी हुई है।

ई.

ए. एस. यू. बी. एम. आई. एस. आई. एन. CR.A.NO. 126/87:

21. श्री जेठमलानी, आपराधिक अपील सं. बिहार राज्य की ओर से पेश हो रहे हैं।126 1987 ने विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।जबकि उक्त मामले के तथ्यों पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों को रद्द करना सही काम था- और यही कारण है कि हम सहमत हुए

च

उपरोक्त दो रिट याचिकाओं के साथ-साथ इस अपील का भी निपटारा करें-उन्होंने खुद को मुख्य रूप से कानून के प्रश्नों तक ही सीमित रखा।उनकी प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

!

"1. संविधान निर्माता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में छठे संशोधन के प्रावधानों से अवगत थे।

जी.

एक 'अभियुक्त' के अधिकार को तेजी से मुकदमा चलाने के लिए संदर्भित करता है।फिर भी इसे भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया था।और गोपालन बनाम के रूप में लंबा।

मद्रास राज्य ने भारत में इस क्षेत्र को संभाला, केवल दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के रूप में त्वरित मुकदमा उपलब्ध था।

संभव हुआ।किसी भी कार्यवाही को कभी रद्द नहीं किया जा सकता था

विलम्ब का आधार।उचित शिकायत किए जाने या स्वतः संज्ञान लेने पर,

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]।349

अदालत हमेशा एक अदालत में स्थानांतरण के आदेशों सहित एक निचली अदालत को उपयुक्त निर्देशों द्वारा त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर सकती है जहां शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सकता है।

2. मेनका गांधी के मामले में इस अदालत के फैसले के साथ, अनुच्छेद 21 को एक नई सामग्री मिली।अपराध की सजा से संबंधित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए।हुसैन आरा खातून और बाद में बी के फैसलों ने अनुच्छेद 21 से एक तथाकथित 'त्वरित परीक्षण का अधिकार' लिखा है।यह एक सुविधाजनक और आत्म-व्याख्यात्मक वर्णन दोनों है।लेकिन ऐसा नहीं है कि छठे संशोधन के अधिकार से जुड़ी हर घटना को भारतीय कानून में पढ़ा जाना चाहिए।यू. एस. ए. में, अधिकार व्यक्त और अयोग्य है।भारत में यह न्याय और निष्पक्षता का केवल एक घटक है।भारतीय अदालतों को कई अन्य हितों के साथ अभियुक्त के लिए सी न्याय और निष्पक्षता का मिलान करना पड़ता है जो सम्मोहक और सर्वोपरि हैं।

(3) अनुच्छेद 21 का इतना अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि यह निर्देशात्मक सिद्धांतों और एक अन्य मौलिक अधिकार अर्थात डी.

अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार।अभियुक्त के वर्ग और चरित्र और उसके अपराध की प्रकृति, एक निजी अभियोजक की कठिनाइयों और सरकार के झुकाव के आधार पर विलंब की अवधारणा पूरी तरह से अलग होनी चाहिए।

ई.

4. अदालत को विधायी नीति का सम्मान करना चाहिए जब तक कि नीति असंवैधानिक न हो।

सीमित सीमा कानून, हालांकि वे आपराधिक पक्ष में हैं, इन पर लागू नहीं होते हैंः

च

(क) 3 वर्ष से अधिक कारावास के साथ दंडनीय गंभीर अपराध;

((ख) सभी आर्थिक अपराध।

जी.

इन दोनों कारणों से उच्च लोक सेवकों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार सुरक्षित नहीं है।

5. त्वरित सुनवाई का अधिकार मुकदमा न चलाने का अधिकार नहीं है।दूसरा, यह केवल अभियोजक पर एक दायित्व पैदा करता है कि वह उचित समय के भीतर मुकदमे के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे।

एच.

इसका मतलब है कि बिना किसी देरी के उसकी चालाकी या

क.

दोषपूर्ण लापरवाही।

6. मुकदमे द्वारा लिए गए समय की वास्तविक अवधि पूरी तरह से अप्रासंगिक है।प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अदालत को एक संतुलनकारी कार्य करना होता है।इसे कई कारकों पर विचार करना पड़ता है, जिनमें से कुछ अभियुक्त के पक्ष में, कुछ अभियोजक के पक्ष में और अन्य पूरी तरह से तटस्थ होते हैं।प्रत्येक

बी.

निर्णय तदर्थ होना चाहिए।समय की कोई बाहरी सीमा निर्धारित करना न तो अनुमत है और न ही संभव है और न ही वांछनीय है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है।हमारी अदालत ने भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया है।इस तरह के न्यायिक कानून की कोई मिसाल नहीं है।

एस.

देने में निम्नलिखित प्रकार की देरी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

त्वरित सुनवाई से इनकार करने की याचिका का प्रभावः

(ए) न्यायालय कैलेंडर की भीड़, न्यायाधीशों की अनुपलब्धता, या अन्य परिस्थितियों के कारण पूरी तरह से देरी

एक्स

अभियोजक का नियंत्रण।

डी.

(ख) विलम्ब स्वयं अभियुक्त द्वारा न केवल स्थगन की मांग के कारण हुआ, बल्कि कानूनी उपकरणों के कारण भी हुआ, जिसका अभियोजक को विरोध करना पड़ता है।

(ग) आदेशों के कारण होने वाली देरी, चाहे वह अभियुक्त द्वारा प्रेरित हो या

ई.

अपील या संशोधन या अन्य की आवश्यकता वाले न्यायालय के नहीं

उचित कार्रवाई या कार्यवाही।

(डी) अभियोजक की वैध कार्रवाइयों के कारण देरी, उदाहरण के लिए, एक प्रमुख गवाह प्राप्त करना जिसे रास्ते से बाहर रखा जाता है या अन्यथा प्रक्रिया या उपस्थिति या एक प्रमुख दस्तावेज का पता लगाने से बचता है या

च

विदेश से साक्ष्य प्राप्त करना।

7. विलंब का आमतौर पर अभियुक्त द्वारा स्वागत किया जाता है।वह गणना में देरी को स्थगित कर देता है।यह अभियोजन पक्ष की उसके खिलाफ मामला साबित करने की क्षमता को बाधित कर सकता है।इस बीच, वह अपराधों में लिप्त होने के लिए स्वतंत्र रहता है।एक अभियुक्त इस याचिका को नहीं उठा सकता है यदि उसने कभी नहीं किया है।

जी.

त्वरित सुनवाई की मांग के लिए कदम उठाए गए।एक याचिका कि उसके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी जाए क्योंकि देरी हुई है

यदि रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने देरी को स्वीकार किया और कभी भी शीघ्र निपटान के लिए नहीं कहा।भारत में मांग नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।किसी को भी यह शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया गया था जब उसने कभी इसकी मांग नहीं की थी।

एच.

* = ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

351

8. 'त्वरित परीक्षण' का मूल कारावास से सुरक्षा है।एक अभियुक्त जिसे कभी कैद नहीं किया गया है, वह शायद ही कभी शिकायत कर सकता है।किसी भी तरह से, उसे कुछ और बहुत मजबूत पूर्वाग्रह दिखाना चाहिए।अधिकार किसी अभियुक्त को होने वाले सभी प्रतिकूल प्रभावों से नहीं बचाता है।

देरी से।इसकी मुख्य चिंता स्वतंत्रता की हानि है।

9. पूर्वाग्रह की संभावना पर्याप्त नहीं है।वास्तविक पूर्वाग्रह होना चाहिए।बी ने साबित किया।

10. याचिका निर्विवाद रूप से और अटूट रूप से मामले के गुण-दोष के साथ मिश्रित है।तथ्यों के पूर्ण ज्ञान के बिना पूर्वाग्रह का पता लगाना संभव नहीं है।याचिका का मूल्यांकन पहले ट्रायल सी द्वारा किया जाना चाहिए।

अदालत।

डब्ल्यू. पी. में प्रस्तुतियाँ। नहीं।268/87 :

श्री अशोक सेन रिट याचिका सं. में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए।268 1 में से

1987 श्री पी. पी. राव के तर्क का समर्थन किया और कहा कि याचिकाकर्ता रंजन द्विवेदी के खिलाफ 15 साल से अधिक समय से लंबित अभियोजन को रद्द कर दिया जाना चाहिए।विद्वान वकील ने कई विशेषताओं पर जोर दिया

आई।

विशेष रूप से मामलाः

(क) सी. बी. आई. द्वारा लगाए गए झूठे निहितार्थ के आरोप और

बिहार पुलिस (सी. आई. डी.) एक दूसरे के खिलाफ;

ई.

(ख) वे परिस्थितियाँ जिनमें सरकारी गवाह विक्रम का बयान दर्ज किया गया था, जिस तरह से उसे पुरस्कृत किया गया था और बाद में उसे वापस लिया गया था;

(ग) श्री ताराकुंडे की रिपोर्ट; और

च

(घ) जिस तरीके से अदालत में अभियोजन चलाया गया था, जिसमें कार्यवाही को जानबूझकर आगे बढ़ाना भी शामिल था।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह एक विशिष्ट रूप से उपयुक्त मामला है जिसमें आरोप और सभी

अब तक की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

जी.

23. श्री राम जेठमलानी ने वरिष्ठ ए. के. सेन की दलीलों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियोजन 1975 से लंबित है और अभी तक नहीं हुआ है।

अब तक समाप्त।उन्होंने कहा कि इस देरी के लिए केवल अभियोजन पक्ष ही जवाब दे सकता है न कि आरोपी।उन्होंने निम्नलिखित तथ्यों को हमारे ध्यान में लायाः

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

एच 352

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. हालाँकि याचिकाकर्ता को 6.7.1975 पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे 19.12.1976 तक इस मामले में पटना की अदालत में पेश नहीं किया गया था।इस सब के दौरान, यह याचिकाकर्ता को पटना अदालत के समक्ष पेश किए बिना और बिना नोटिस दिए भी उसकी रिमांड की अवधि बढ़ा रही थी।

क.

↑

उसे।जब तक उन्हें दिसंबर, 1976 में पटना की अदालत में पेश नहीं किया गया, तब तक याचिकाकर्ता को यह भी पता नहीं था कि उन्हें एल. एन. मिश्रा हत्या मामले में भी फंसाया गया था।आरोप-पत्र दिसंबर, 1975 में ही दाखिल किया गया था।इससे बहुत पहले, अभियुक्त इसके हकदार हो गए थे -

आई. पी. आर. की धारा 167 के तहत रिहाई।पी. सी. लेकिन वह इन सभी तथ्यों से अवगत नहीं थे और इसलिए, उन्होंने उक्त अधिकार का दावा नहीं किया।भले ही उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश रे से संबंधित मामले में उनकी दोषसिद्धि के

खिलाफ दायर अपील में जमानत दे दी थी, लेकिन एल. एन. मिश्रा मामले में उनके निहितार्थ के कारण उन्हें रिहा नहीं किया गया था।याचिकाकर्ता 30.3.1978 तक जेल में रहा, जब इस अदालत ने जमानत दे दी।याचिकाकर्ता को 21.1.1977 (दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने की तारीख) से 30.3.1978 तक कैद करना अवैध और असंवैधानिक है।यह पूरी कार्यवाही को दूषित करता है।

एस.

डी.

2. दिसंबर, 1975 में आरोप पत्र दायर करने की तारीख से लेकर 1979 में मामला दिल्ली स्थानांतरित होने तक, अभियोजन पक्ष मामले को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है।इसने यह नहीं बताया है कि वह इन तीन वर्षों में क्या कर रहा था-किस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को अवैध रूप से कैद किया गया था।

ई.

3. अभियोजक न केवल उन दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जिन पर उसने भरोसा किया है, बल्कि उन सभी दस्तावेजों की भी आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जो अभियुक्त के लिए भी अनुकूल हो सकते हैं।यह दायित्व अधिवक्ता अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 16 से और अभियोजक के कार्यालय से जुड़े कार्यालय और कर्तव्यों की प्रकृति से आता है। उपरोक्त नियम 16 अभियोजक को इससे प्रतिबंधित करता है -

च

अभियुक्त के लिए अनुकूल सामग्री को दबाना।

4. श्री आहूजा सी. बी. आई. के मुख्य जांच अधिकारी थे। उन्होंने ही अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर से पूछताछ की थी और 21 फरवरी, 1975 को अरुण कुमार ठाकुर का इकबालिया बयान दर्ज कराया था।इस स्वीकारोक्ति के अनुसार,

जी.

उन्होंने कहा कि बिहार के एक विशेष राजनीतिक नेता के कहने पर दो अभियुक्तों ने हत्या को अंजाम दिया।ये तथ्य पटना अदालत के समक्ष उनके द्वारा दायर आवेदनों से स्थापित किए गए हैं जो अब इस रिट याचिका के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।लेकिन फिर जून, 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद मामले ने अचानक एक अलग मोड़ ले लिया।मूल अभियुक्तों को यह कहते हुए छोड़ दिया गया कि वे निर्दोष हैं

एच.

.)

न.

ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

353

और पूरा ध्यान अब आनंद मार्ग पर स्थानांतरित हो गया।सितंबर में, ए 1975 आहूजा ने अदालत में आवेदन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा।ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह दोनों संस्करणों को अदालत के समक्ष रखे ताकि अदालत यह तय करने में सक्षम हो सके कि कौन सा संस्करण सही है।अभियोजन पक्ष अपने पहले संस्करण के संबंध में साक्ष्य को पूरी तरह से दबाने के लिए तैयार नहीं है।

और अकेले दूसरा संस्करण प्रस्तुत करें।यह पूरी तरह से अनुचित है।वास्तव में, बी ने 13 गवाहों से पूछताछ करने का अनुरोध (अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ दिया गया) ठीक इस पहले संस्करण को स्थापित करने के लिए था और यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष छह महीने से अधिक समय से अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर को वास्तविक आरोपी के रूप में खोज रहा है।उक्त 13 गवाहों में से गवाह संख्या 12 और 13 वही आरोपी हैं।याचिकाकर्ता चाहता था कि उन सभी से अदालत के गवाहों के रूप में पूछताछ की जाए ताकि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को उनसे जिरह करने का अवसर मिले।अदालत तब सच्चाई का पता लगाने की स्थिति में होगी।यह अनुरोध अभियोजन पक्ष द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया था जिसने याचिकाकर्ता को दिल्ली

उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया।दिनांकित 13.2.1987 आदेश से पता चलता है कि उक्त संशोधन कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाता है और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लंबित होने के कारण पांच साल की देरी को अभियोजन पक्ष के दरवाजे पर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह याचिकाकर्ता के अदालत के गवाहों के रूप में उक्त 13 गवाहों को राशि देने के उचित अनुरोध के अनुचित विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है।विद्वान वकील ने अदालत के सामने पूरी सच्चाई रखने के लिए अभियोजन पक्ष के कर्तव्य पर जोर देने के लिए कुछ निर्णयों पर भरोसा किया।इनके अनुसार

} 1

वकील ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था कि वह पहले के संस्करण और उस ओर से उनके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य को भी अदालत के समक्ष रखे।उन्होंने भी दो राज्य एजेंसियों के एक-दूसरे पर झूठे एफ का आरोप लगाने के अजीब दृश्य पर जोर दिया।

प्रभाव और फ्रेम-अप।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा श्री डी. सी. अग्रवाल (देरी तीन महीने की है) के सामने ही अभियुक्त को गद्य में काटने पर जोर देने के कारण हुई देरी, हालांकि छोटी है, अभियोजन पक्ष के मलोवो का संकेत देती है।

लेंस।यह अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित करता है और एक अतिरिक्त आधार है जी

कार्यवाही को रद्द करने के लिए।

24. सी. बी. आई. की ओर से पेश हुए विद्वान महान्यायवादी ने पहली बार में कहा कि इस अदालत को त्वरित सुनवाई के अधिकार से संबंधित कोई मानदंड या दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं करने चाहिए।उनके अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता में पर्याप्त प्रावधान हैं जो एच 354 के लिए दिशानिर्देशों के रूप में काम करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना।उन्होंने अनुरोध किया कि इस पीठ के समक्ष रखे गए मामलों का बिना कोई सामान्य प्रस्ताव रखे गुण-दोष के आधार पर निपटारा किया जाए।उन्होंने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 एक पर्याप्त उपाय है।यह एक ऐसे अभियुक्त द्वारा लागू किया जा सकता है जिसे त्वरित मुकदमे से वंचित कर दिया गया है।उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के पास आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है यदि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का मार्ग आवश्यक पाया जाता है।बी में आपराधिक मामले के समापन में अनुचित देरी अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उक्त प्रावधान के तहत इसे रद्द किया जा सकता है।उन्होंने हमें पटना अदालत और दिल्ली अदालत दोनों में इस मामले की पूरी कार्यवाही के बारे में बताया और कहा कि अभियोजन पक्ष के खिलाफ देरी का आरोप पूरी तरह से निराधार है और वास्तव में देरी आरोपी द्वारा ही की गई है।उन्होंने कहा कि आरोपी बार-बार कई तुच्छ अंतर्वर्ती आवेदन दायर कर रहे थे और कई रणनीति अपनाकर मुकदमे को स्थगित करने की प्रार्थना कर रहे थे।उदाहरण के लिए, अक्सर एक अभियुक्त स्वयं अनुपस्थित रहता था और फिर दूसरा अभियुक्त कहता था कि उस अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए।भले ही उनका स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन वे बीमार होने की गुहार लगाते हुए अदालत में उपस्थित नहीं हुए।इस तथ्य को पटना जेल के जेलर ने एक से अधिक बार प्रमाणित किया है।उनके वकील भी सप्ताह में पाँच दिन डी पर मुकदमा चलाने में अदालत का सहयोग नहीं कर रहे थे।वे सप्ताह में केवल तीन दिन चलने के लिए तैयार थे और वह भी पूरे दिन के लिए नहीं।सबूत बहुत बड़े हैं और हजारों दस्तावेज हैं।उन्होंने कहा कि परिस्थितियों में, स्वाभाविक रूप से मुकदमे में काफी समय लगा।अभिलेख पर सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि अभियोजन पक्ष हमेशा मुकदमे को तेजी से समाप्त करने के लिए उत्सुक था और वास्तव में मुकदमा रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ा, जिसमें 151 गवाहों से पूछताछ की गई।ई इसने 1986 में अपना मामला बंद कर दिया।फिर अभियुक्त कुछ गवाहों से पूछताछ करने के लिए एक आवेदन के साथ आगे आए जो पूरी तरह से अनावश्यक थे और जिन्हें अभियोजन पक्ष ने स्वीकार कर लिया था।जब विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा इसे सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया, तो वे उच्च न्यायालय गए और आगे की सभी कार्यवाही प्राप्त की और मुकदमे पर रोक लगा दी।इस प्रकार, केवल अभियुक्त और अभियुक्त ही हैं जो मुकदमे को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए, उनके नियमों के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकते हैं।

एस.

च

→

विद्वत महान्यायवादी ने तर्क दिया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार।

25. श्री चटर्जी सी. ए. सं. 3811/90 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए।

श्री पी. पी. राव की दलीलों का समर्थन किया, जबकि सी. एम. पी. संख्या में आर. एस. नायक की ओर से श्री राजीव धवन ने आम तौर पर जी श्री जेठमलानी की दलीलों का समर्थन किया।हस्तक्षेपकर्ता महिला दक्षत समिति की ओर से उपस्थित सुश्री रानी जेठमलानी ने अपने लिखित तर्कों में महिलाओं के दृष्टिकोण से इस अधिकार के महत्व पर जोर दिया।

26. त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जैसा कि यू. एस. एच. संविधान के छठे संशोधन में स्पष्ट रूप से इस अधिकार को मान्यता दी गई है।छठा संशोधन ए. आर. एंटूले v.

आर. एस. नायक (रेड्डी, जे.)

355

अन्य बातों के साथ घोषणा करता है कि 'सभी आपराधिक अभियोजनों में अभियुक्त को त्वरित और सार्वजनिक मुकदमे का अधिकार प्राप्त होगा'।यह पाँचवें संशोधन के अतिरिक्त है जो अन्य बातों के साथ घोषणा करता है कि "किसी भी व्यक्ति को जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा", जो मोटे तौर पर अनुच्छेद 21 (और अनुच्छेद 31 का खंड 1, जब से हटा दिया गया है) के अनुरूप है।ए. के. गोपालन बनाम में यह चूक और होल्डिंग।मद्रास राज्य [1950] एस. सी. आर. 88 संभवतः बताता है कि इस अधिकार का दावा या अनुच्छेद 21 से बहने वाले मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता तब तक क्यों नहीं दी गई जब तक कि गोपालन बी इस क्षेत्र में थे।एक बार आर. सी. कूपर (1970 एस. सी. 564) में गोपालन का शासन समाप्त हो गया और इसका सिद्धांत मेनका गांधी (1978 एस. सी. 597) में अनुच्छेद 21 तक विस्तारित हो गया।यह एक ऐसी शक्ति और जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए आया जिसकी अब तक कल्पना नहीं की गई थी।मेनका गांधी के उपवास के बाद इस अदालत के रचनात्मक फैसलों ने इस अनुच्छेद को एक नया अर्थ दिया और इसकी विषय-वस्तु और अर्थ का विस्तार किया।हालाँकि यह उन सभी निर्णयों को गिनने का स्थान नहीं है, लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि हुसैनारा खातून मामलों में इस अदालत की राय वर्ष में तय हुई थी।1979 , यह घोषणा करना कि त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है और इस प्रकार अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, एक है

क.

एस.

उनके बीच,

डी.

27. गोपालन में, इस अदालत ने माना कि निवारक से संबंधित कानून

निरोध संविधान के अनुच्छेद 22 में पाया जाता है और यह कि अनुच्छेद 22 उस संबंध में एक स्व-निहित संहिता है।यह भी देखा गया कि अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात कानून को अनुच्छेद 19 में तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों अनुच्छेद (21 और 19) दो अलग-अलग धाराओं का गठन करते हैं।मेनका गांधी में, दो अलग-अलग धाराओं का गठन करने वाले अनुच्छेद 21 और 19 के संबंध में गोपालन में टिप्पणियों को या तो आज्ञाकारी या गलत माना गया है, जैसा भी मामला हो।यह इंगित किया गया है कि वर्षों से इस न्यायालय ने इस विचार को स्वीकार किया है कि संविधान-और विशेष रूप से भाग III द्वारा गारंटीकृत कई मूलभूत अधिकारों-को एक अभिन्न समग्र के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें विषय के संभावित ओवरलैपिंग के साथ-इसके विभिन्न प्रावधानों द्वारा संरक्षित किए जाने की मांग की जाती है।बेग, मुख्य न्यायाधीश ने [1978] 2 एस. सी. आर. के पृष्ठ 648 पर निम्नलिखित शब्दों में विचार व्यक्त किया।:

ई.

आई.

1

च

" संविधान के भाग III में निहित विभिन्न मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद पूरी तरह से अलग नहीं हैं।

अधिकारों की धाराएँ जो कई बिंदुओं पर नहीं मिलती हैं।वे सभी हैं।

जी.

संविधान में एक एकीकृत योजना के भाग।उनके जल को निर्बाध और निष्पक्ष न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (न केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की, बल्कि संगठन, आंदोलन, व्यवसाय या व्यवसाय के साथ-साथ उचित संपत्ति के अधिग्रहण और कब्जे की भी), समानता (स्थिति और एच 356) के उस भव्य प्रवाह का गठन करने के लिए मिश्रित होना चाहिए।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

>

अवसर, जो व्यक्तियों, समूहों और वर्गों के बीच अनुचित या अनुचित भेदभाव का अभाव दर्शाता है), और बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन), जिसकी कल्पना हमारा संविधान करता है।मानव स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं को उनकी सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए अलग करना न तो यथार्थवादी है और न ही फायदेमंद है, लेकिन इस तरह के संरक्षण के उद्देश्यों को ही पराजित करेगा।

क.

च

जे. भगवती ने निम्नलिखित शब्दों में यही विचार रखाः

" इसलिए, कानून को अब अच्छी तरह से तय किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 को बाहर नहीं करता है और भले ही किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कोई कानून हो।

एस.

और परिणामस्वरूप अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है, जहां तक यह अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करता है या छीनता है, उस अनुच्छेद की चुनौती का सामना करना होगा।आर. सी. कूपर के मामले, शंभू नाथ सरकार के मामले और हरधन सहाय के मामले में निर्णय के बाद इस प्रस्ताव पर अब कोई विवाद नहीं हो सकता है।अब, यदि कोई कानून वंचित करता है

डी.

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' वाले व्यक्ति और अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर उस उद्देश्य के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त एक या अधिक मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरा उतरना होगा जो किसी दी गई स्थिति में लागू हो सकता है, पूर्व परिकल्पना यह भी होनी चाहिए कि वह अनुच्छेद 14 के संदर्भ में परीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।" .

ई.

विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेदों के बीच अभिन्न संबंध की ओर इशारा किया

14 और 21 निम्नलिखित शब्दों में: "अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करता है।निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है।तर्कसंगतता का सिद्धांत, जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से, एक आवश्यक तत्व है

च

समानता या गैर-मनमानी अनुच्छेद 14 में एक व्यापक सर्वव्यापीता की तरह व्याप्त है और अनुच्छेद 21 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए।यह "सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए; अन्यथा, यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और अनुच्छेद 21 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। "

जी.

28. यह निर्णय स्पष्ट शब्दों में स्थापित करता है कि अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात विधि और प्रक्रिया को अनुच्छेद 19 और 14 के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए।यह स्थापित करता है कि अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होनी चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होनी चाहिए।यह एच निष्पक्षता और तर्कसंगतता का यह सिद्धांत है जिसे इसके दायरे में लेने के रूप में माना गया था।

जे. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.] '357

त्वरित सुनवाई का अधिकार।पहले हुसैनारा खातून निर्णय में (1979 (3)

क.

एस. सी. आर. 169) जे. भगवती ने निम्नलिखित टिप्पणी की:7 " हम सोचते हैं कि हमारे संविधान के तहत भी, हालांकि त्वरित सुनवाई को विशेष रूप से एक मौलिक अधिकार के रूप में गिना नहीं गया है, यह अनुच्छेद 21 के व्यापक विस्तार और सामग्री में निहित है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम में व्याख्या की गई है।भारत संघ।हमने उस बी मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं होने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, सिवाय उस अनुच्छेद की आवश्यकता के कि किसी प्रक्रिया की कुछ झलक कानून द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, लेकिन यह कि प्रक्रिया "उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण" होनी चाहिए।यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी प्रक्रिया के तहत अपनी स्वतंत्रता से वंचित है जो "उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत" नहीं है, तो इस तरह का वंचित करना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

अनुच्छेद 21 और वह इस तरह के मौलिक अधिकार को लागू करने और अपनी राहत सुनिश्चित करने का हकदार होगा।अब स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया "उचित या न्यायसंगत" नहीं हो सकती है जब तक कि वह प्रक्रिया ऐसे व्यक्ति के अपराध के निर्धारण के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं करती है।ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो डी

यह सुनिश्चित करना कि एक उचित रूप से त्वरित सुनवाई को 'उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत' माना जा सकता है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि त्वरित सुनवाई, और त्वरित सुनवाई से हमारा मतलब है कि एक त्वरित त्वरित सुनवाई, न्याय प्रणाली का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है।

अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार।ई.

हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर बाद में दिया जाना बाकी है।पूछा गया सवाल यह था:इस अधिकार से इनकार करने का क्या परिणाम है?क्या यह आवश्यक रूप से आरोपों/मुकदमे को रद्द करने का परिणाम है?उस प्रश्न पर हम अलग से विचार करेंगे लेकिन इसका क्या महत्व है, यह निर्णय निम्नलिखित प्रस्तावों को स्थापित करता है:

च

(1) त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के व्यापक विस्तार और विषय-वस्तु में निहित है।

(2) कि जब तक कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं करती है, तब तक इसे उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है।त्वरित सुनवाई और निरोध से स्वतंत्रता मानवाधिकारों और बुनियादी जी स्वतंत्रताओं का

हिस्सा है और यह कि एक न्यायिक प्रणाली जो बिना मुकदमे के पुरुषों और महिलाओं को लंबे समय तक कैद रखने की अनुमति देती है, उसे ऐसे विचाराधीन लोगों के मानवाधिकारों से वंचित माना जाना चाहिए।

अभियुक्त के विद्वान वकील ने विशेष रूप से भगवती, जे की राय से निम्नलिखित अंश पर भरोसा किया।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच 358

" कानूनी और न्यायिक प्रणाली की एक और कमजोरी भी है

क.

वाई.

जो विचाराधीन कैदियों को न्याय से इस घोर इनकार के लिए जिम्मेदार है और यह मामलों के निपटारे में कुख्यात देरी है।यह कानूनी और न्यायिक प्रणाली पर एक बुरा प्रतिबिंब है कि एक आरोपी का मुकदमा लंबे वर्षों तक भी शुरू नहीं होना चाहिए।यहां तक कि मुकदमे की शुरुआत में एक साल की देरी भी काफी खराब है; यह कितना बुरा हो सकता है जब देरी 3 या 5 या 7 या 10 साल तक हो।त्वरित मुकदमा आपराधिक न्याय की भावना का है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मुकदमे में देरी अपने आप में न्याय से इनकार है।

29. दूसरे हुसैनारा खातून मामले, [1979] 3 एस. सी. आर. 393 में, इस अदालत सी ने निर्देश दिया कि जिन विचाराधीन कैदियों के खिलाफ धारा 468 में प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, उनके खिलाफ बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जा सकता है।इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्तियों को आगे कोई भी हिरासत में रखना गैरकानूनी और अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता।

डी.

तीसरे हुसैनारा खातून मामले [1979] 3 एस. सी. आर. 532 में, जे. भगवती ने कहाः

" राज्य वित्तीय या प्रशासनिक अक्षमता का अनुरोध करके अभियुक्त को त्वरित सुनवाई प्रदान करने के अपने संवैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता है।यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य एक संवैधानिक जनादेश के तहत है

ई.

त्वरित परीक्षण और इस उद्देश्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह राज्य द्वारा किया जाना चाहिए।लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में इस न्यायालय का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह राज्य को आवश्यक निर्देश जारी करके त्वरित सुनवाई के लिए अभियुक्त के मौलिक अधिकार को लागू करे, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई करना शामिल हो सकता है, जैसे कि

च

और जांच तंत्र को मजबूत करना, नई अदालतों की स्थापना, नए अदालतों का निर्माण, अदालतों को अधिक कर्मचारी और उपकरण प्रदान करना, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए गणना किए गए अन्य उपाय।

30. बिहार राज्य में v.उमा शंकर केत्रीवाल और अन्य।, [1981] 2 एस सी आर।

जी.

402 अप्रैल, 1960 में पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि प्रत्यर्थी फर्म ने कोटा धारकों को वितरित करने के लिए बड़ी मात्रा में जी. सी. शीट का दुरुपयोग किया था।जाँच के बाद 1962 में मजिस्ट्रेट को एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिन्होंने

जनवरी, 1963 में मामले का संज्ञान लिया।सितंबर, 1967 में प्रत्यर्थियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।इसके बाद, एच मामले की प्रगति बहुत धीमी थी।1979 में उत्तरदाताओं ने ए. आर. एंटूले बनाम के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया।

आर. एस. नायक [रेड्डी, जे.] 359

उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करना।उच्च न्यायालय ने ए की कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि पुलिस रिपोर्ट में प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी सबूत का खुलासा नहीं किया गया है और 1963 में शुरू हुआ और 1979 में अभी भी चल रहा अभियोजन अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।राज्य ने इस अदालत में अपील की।यह न्यायालय राज्य से सहमत होने के लिए इच्छुक था कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया पहला आधार टिकाऊ नहीं हो सकता है, लेकिन उसने बी दूसरे आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की।इस अदालत ने टिप्पणी कीः

" हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मुकदमे में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है, भले ही कम से कम 20 साल बीत चुके हों।इस तरह के निष्कासन का अर्थ है न केवल आर्थिक रूप से बल्कि चिंता के अलावा सी मामले पर लगातार ध्यान देने और अदालत में बार-बार पेश होने के माध्यम से भी अभियुक्त को काफी परेशान करना।यह अच्छी तरह से हो सकता है कि प्रतिवादी स्वयं मामले की धीमी गति के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार थे क्योंकि ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए कुछ आदेशों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी, लेकिन फिर उस अवधि की एक सीमा होनी चाहिए जिसके लिए डी

आपराधिक मुकदमेबाजी को मुकदमे के चरण में जारी रखने की अनुमति है।मामले के इस दृष्टिकोण में, हम वर्तमान मामले को अपने हस्तक्षेप के लिए उचित नहीं मानते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि हम महसूस करते हैं कि आरोप एक ऐसे अपराध के होने का खुलासा करते हैं जिसे हम काफी गंभीर मानते हैं।

ई.

31. खदरा पहाड़िया बनाम।बिहार राज्य [1983] 2 एस. सी. सी. 104, इस न्यायालय ने हुसैनारा खातून मामले के सिद्धांत की फिर से पुष्टि की और घोषणा की किःकोई भी अभियुक्त जिसे त्वरित विचारण के इस अधिकार से वंचित किया जाता है, वह ऐसे अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से इस न्यायालय से संपर्क करने का हकदार है और इस न्यायालय को अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए राज्य सरकारों और अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश देने की शक्ति है।

न्यायालय ने बिहार सरकार और उच्च न्यायालय को त्वरित निपटान के लिए अतिरिक्त अदालतें बनाने के निर्देश सहित आवश्यक निर्देश भी दिए।

लंबे समय से लंबित मामले।32. इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम में इस अधिकार की प्रयोज्यता पर फिर से विचार किया। चंपालाल पुंजाजी शाह, [1982] 1 एस. सी. आर. 299.चिन्नाप्पल रेड्डी, जे. अपने और ए. पी. सेन और बहरुल इस्लाम, जे. जे. के लिए बोल रहे हैं।हुसैनारा खातून के सिद्धांत की पुष्टि की और पालन करने के लिए आगे बढ़ेः

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

एच 360

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" इस सवाल को तय करने में कि क्या इनकार किया गया है

क.

त्वरित विचारण के अधिकार पर न्यायालय इस बात पर विचार करने का हकदार है कि क्या प्रतिवादी स्वयं देरी के एक हिस्से के लिए जिम्मेदार था और क्या वह देरी के कारण अपने बचाव की तैयारी में पूर्वाग्रह से ग्रस्त था।न्यायालय को इस बात पर भी विचार करने का अधिकार है कि क्या विलंब अनजाने में हुआ था, जो न्यायालय में भीड़भाड़ के कारण हुआ था या अभियोजकों के कम कर्मचारियों के कारण हुआ था।स्ट्रंक वी.संयुक्त राज्य अमेरिका इस बिंदु पर एक शिक्षाप्रद मामला है।जैसा कि पहले हुसैन आरा मामले (उपरोक्त) में बताया गया है, त्वरित सुनवाई का अधिकार भारत में स्पष्ट रूप से गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में निहित है जिसे अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया है।21 संविधान से।जबकि एक त्वरित परीक्षण एक निष्पक्ष परीक्षण का एक निहित घटक है, इसके विपरीत आवश्यक रूप से सच नहीं है।एक विलंबित परीक्षण अनिवार्य रूप से एक अनुचित परीक्षण नहीं है।विलम्ब स्वयं अभियुक्त की

रणनीति या आचरण के कारण हो सकता है।हो सकता है कि देरी से अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ हो।यह सवाल कि क्या विलंबित मुकदमे के आधार पर दोषसिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।यदि अभियुक्त को अपने आचरण में पूर्वाग्रहपूर्ण पाया जाता है

एस.

डी.

बचाव पक्ष और यह कहा जाएगा कि इस प्रकार अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर से वंचित कर दिया गया था, दोषसिद्धि को निश्चित रूप से छोड़ना होगा।लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिखाया जाता है और अदालत को यह अनुमान लगाने का अधिकार देने वाली कोई परिस्थितियां नहीं हैं कि आरोपी को पूर्वाग्रह से ग्रस्त किया गया था, तो केवल विलंबित मुकदमे के आधार पर दोषसिद्धि को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं होगा।

ई.

अदालत ने तब उक्त सिद्धांतों के आलोक में अपने समक्ष मामले के तथ्यों की जांच की और पाया कि आरोपी स्वयं देरी के एक उचित हिस्से के लिए जिम्मेदार था और वह यह भी स्थापित करने में असमर्थ रहा है कि वह कैसे था।

च

देरी के कारण अपने बचाव के आचरण में पूर्वाग्रह।न्यायालय ने अपराध की प्रकृति को भी ध्यान में रखा, अर्थात् एक आर्थिक अपराध जो देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालता है और कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।तदनुसार, इसने उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया।अपने फैसले के दौरान, न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी ने कहा कि "देरी एक ज्ञात जी बचाव रणनीति है" और यह भी कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर है, वह अभियोजन को यथासंभव लंबे समय तक लंबित रखने के लिए उसी रणनीति का सहारा ले सकता है।उन्होंने कहाः

" त्वरित सुनवाई को किसी और चीज के प्रमाण के साथ या उसके बिना अस्वीकार करने से पूर्वाग्रह और न्याय से इनकार का अपरिहार्य अनुमान लग सकता है।बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जाना किसी व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रह है।यह है।

एच.

एक आदमी के प्रति पूर्वाग्रह एक निष्पक्ष मुकदमे से वंचित किया जाना "। ए. आर. एंटूले बनाम

आर. एस. नायक [आर. ई. डी. टी., जे.]

361

यह मामला समस्या के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है।क.

इस निर्णय के अनुसार कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित करना संभव नहीं है।

:

त्वरित सुनवाई से इनकार करने की शिकायत का न्याय करने में और यह कि निर्णय लेने से पहले मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार हैंः(1) क्या अभियुक्त देरी के लिए जिम्मेदार है; बी (2) क्या वह किसी भी तरह से इस तरह की देरी से पूर्वाग्रहित है, निश्चित रूप से, कुछ मामलों में अभिवचन स्वयं पूर्वाग्रह के बराबर हो सकता है; (3) अपराध की प्रकृति जिसके साथ अभियुक्त पर आरोप लगाया जाता है; सी

33. टी. वी. वथीस्वरन बनामतमिलनाडु राज्य, [1983] 2 एस. सी. आर. 328, इस न्यायालय ने फिर से त्वरित मुकदमे के अधिकार के महत्व को दोहराया और इसे दोषसिद्धि के बाद के चरण तक बढ़ा दिया।यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृत्युदंड को पूरा करने में अनुचित देरी से अभियुक्त को आजीवन कारावास की कम सजा की माँग करने का अधिकार मिलता है।यह राय मौत की सजा पाए व्यक्ति की अपार मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और मानसिक यातना पर आधारित है।हालांकि यह डी निर्णय समाप्त हो गया था-बाद में एक संविधान पीठ द्वारा फैसला सुनाया गया था, यह उस सीमित सीमा तक प्रासंगिक है जो हुसैन आरा खातून में प्रतिपादित त्वरित मुकदमे के अधिकार की पुष्टि करता है।

34. एस. गुइन एंड ओआरएस में।वी.ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड, [1985] सप्लीमेंट।3 एस. सी. आर. 818

ई आई

अपीलार्थियों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 एडी के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 341 के तहत मुकदमा चलाया गया था।का पदार्थ

आरोप यह था कि उन्होंने बिना किसी उचित कारण के बैंक के अधिकारियों को बैंक की एक शाखा के परिसर में कानूनी रूप से प्रवेश करने से रोका था और सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के लेनदेन में भी बाधा डाली थी।उन्हें निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था, जिसके बाद प्रतिवादी/बैंक ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसने इसे छह साल की अवधि के बाद स्वीकार कर लिया और मामले को फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया।इस अदालत के समक्ष रिमांड के आदेश पर सवाल उठाया गया और उसे दरकिनार कर दिया गया।ई. एस. वेंकटरमैया, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियांःप्रासंगिक हैंः

च

" मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय के फैसले को देखने के बाद हमें लगता है कि जो भी त्रुटि हुई होगी

मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया, मामले की परिस्थितियों में, यह।

जब उच्च न्यायालय के फैसले से लगभग छह साल पहले बरी करने का आदेश पारित किया गया था, तब उच्च न्यायालय के लिए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजना उचित और उचित नहीं था।उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील का छह साल तक लंबित रहना इस मामले की एक खेदजनक विशेषता है।इसके अलावा, आदेश एच 362

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क.

पुनः विचारण के निर्देशन के परिणामस्वरूप अपीलार्थियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।हमारा विचार है कि अपीलार्थियों द्वारा किए गए कथित कृत्यों की प्रकृति और अन्य परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को छोड़ने का निर्देश देना चाहिए था, भले ही किसी कारण से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि बरी कर दिया गया है।

गलत था।कथित घटना के लगभग सात साल बाद एक नए मुकदमे के परिणामस्वरूप उत्पीड़न और दुर्व्यवहार होना तय है। न्यायिक प्रक्रिया "।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपराध की प्रकृति सी में मुख्य रूप से न्यायालय के साथ यह निर्देश दिया गया है कि कार्यवाही को आगे जारी नहीं रखा जाना चाहिए।

35. शीला बारसे और ओआरएस में।वी.भारत संघ और अन्य।, [1986] 3 एस. सी. आर. 562, ए.डिवीजन बेंच जिसमें भगवती और आर. एन. मिश्रा, जे.पुनः पुष्टि की कि "त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक मौलिक अधिकार है" और कहा कि "त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का परिणाम यह होगा कि अभियोजन पक्ष स्वयं

इसे इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।इस प्रकार, अदालत ने उस प्रश्न का उत्तर दिया जो न्यायमूर्ति भगवती ने पहले हुसैन आरा मामले में पूछा था।तदनुसार, उन्होंने निर्देश दिया कि जहां तक 7 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के आरोपी बच्चे का संबंध है, एक अवधि

ई.

शिकायत दर्ज करने या एफ. आई. आर. दर्ज करने की तारीख से तीन महीने की अवधि को जांच के लिए अधिकतम अनुमेय समय माना जाएगा और आरोप पत्र दाखिल करने से छह महीने की अवधि को उचित अवधि के रूप में माना जाएगा जिसके भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए।यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि यदि इन समय सीमाओं का पालन नहीं किया जाता है, तो बच्चे के खिलाफ मुकदमा रद्द कर दिया जाना चाहिए।

च

36. अब हम रघुबीर सिंह और अन्य के मामले में इस अदालत के फैसले को देख सकते हैं।वी.बिहार राज्य, [1986] 3 एस. सी. आर. 802।इस मामले में, सिमरजीत सिंह मान और कुछ अन्य लोगों ने जमानत के लिए इस अदालत में आवेदन किया और याचिका को रद्द करने के लिए भी।

त्वरित विचारण के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही।यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ताओं का उक्त अधिकार अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाई गई रणनीति से निराश हो रहा था, जिसका एकमात्र उद्देश्य याचिकाकर्ताओं को किसी तरह जेल में रखना था।यह भी तर्क दिया गया कि धारा 121-ए और 124-ए के तहत आरोप तय करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।जे. चिन्नाप्पा रेड्डी ने पुष्टि की कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद एच 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के आयामों में से एक है।संयुक्त राज्य ए. आर. एंटुल बनाम के निर्णयों की जांच करने के बाद।

363

आर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

उच्चतम न्यायालय ने स्ट्रंक बनाम.संयुक्त राज्य अमेरिका, (37 लॉयर्स एडन। दूसरा 56) और विली।क.

माई बार्कर बनाम।जॉन विंगो, (33 वकील एडन।2101 और बेल बनाम में प्रिवी काउंसिल का भी।लोक अभियोजक जमैका के निदेशक, [1985] 2 ए. ई. आर. 585, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रासंगिक प्रश्न पूछेः

" विचार के लिए कई सवाल उठते हैं।क्या कोई देरी हुई?देरी कब तक हुई?क्या मामले की बी प्रकृति, कानूनी सेवाओं की विरल उपलब्धता और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देरी अपरिहार्य थी?क्या देरी अनुचित थी?क्या अभियोजन एजेंसी की जानबूझकर या लापरवाही के कारण देरी हुई थी?क्या बचाव की रणनीति के कारण हुई देरी का कोई हिस्सा था?क्या कारण के कारण देरी अभियोजन और बचाव एजेंसियों के नियंत्रण से बाहर थी?क्या अभियुक्त के पास त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार का दावा करने की क्षमता और अवसर था?क्या इस बात की संभावना थी कि आरोपी को उसके बचाव में तैयार किया गया था?उसके बचाव के आचरण में पूर्वाग्रह की किसी भी संभावना के बावजूद, क्या देरी की अवधि ही अभियुक्त के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिकूल थी?इनमें से कुछ कारकों की पहचान बार्कर बनाम में की गई है।विंगो (ऊपर)।कई अन्य प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं जिनकी हम अभी आसानी से कल्पना नहीं कर सकते हैं।सवाल यह है कि क्या त्वरित सुनवाई का अधिकार जो कला द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।21 उल्लंघन किया गया है अंततः निष्पक्षता का सवाल है

आपराधिक न्याय का प्रशासन भले ही 'निष्पक्ष रूप से कार्य करना' प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सार है (पुनः।एच. के. 1967 (1) सभी ई. आर. 226) और एक 'निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया' वह है जो कला में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति द्वारा दी गई है।21 (मेनका गांधी) "।

इस मामले में विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण व्यावहारिक रूप से एफ है

जैसा कि उनके द्वारा चंपालाल पुंजाजी शाह (ऊपर) में अपनाया गया था, ठीक है कि त्वरित मुकदमा "अंततः आपराधिक न्याय के प्रशासन में निष्पक्षता का सवाल है"।

37. राकेश सक्सेना बनाम।सी. बी. आई., [1987] 1 एस. सी. आर. 173 के माध्यम से, इस अदालत ने इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया कि अपीलार्थी के मामले में छह साल से अधिक के अंतराल के बाद अभियोजन जी का कोई भी आगे जारी रहना, जो केवल बैंक के विदेशी मुद्रा प्रभाग में पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर एक व्यापारी था, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि

.क.

आरोपित अपराध की जटिल प्रकृति।

इसी तरह, श्रीनिवास गोपाल बनाम।केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, एच

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी 364

ए (अब राज्य) [1988] पूरक।1 एस. सी. आर. 477, अदालत ने जांच में देरी और मुकदमा शुरू करने के आधार पर अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया।इस मामले में नवंबर, 1976 में जांच शुरू हुई और सितंबर, 1977 में जांच पूरी होने पर मामला दर्ज किया गया।न्यायालय द्वारा मार्च, 1986 में संज्ञान लिया गया था।इन तथ्यों को कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त माना गया था, विशेष रूप से जब आरोप लगाया गया अपराध बी एक नाबालिग था, अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए को 338 के साथ पढ़ा गया था।38. फिर से टी. जे. स्टीफन और ओरस बनाम में।पारले बॉटलिंग कं. (पी) लिमिटेड और अन्य।,.[1988] 3 एस. सी. आर. 296 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को रद्द करने का उच्च न्यायालय का आदेश (आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के तहत) कानूनी रूप से अस्थिर था, लेकिन बीस साल के अंतराल के बाद अभियोजन शुरू करने और मुकदमा चलाने की अनुमति देना न्याय के हित में नहीं होगा, भले ही अभियुक्तों में से एक स्वयं अपनी दुर्भावनापूर्ण रणनीति के कारण हुई अधिकांश देरी के लिए जिम्मेदार था। इसमें

निर्णय में, अनुच्छेद 21 या त्वरित सुनवाई के अधिकार का कोई संदर्भ नहीं है।आदेश केवल इस तथ्य पर आधारित है कि 20 साल के अंतराल के बाद अभियोजन और मुकदमे को फिर से शुरू करने की अनुमति देना न्याय के हित में नहीं होगा।

डी.

दीवान नौबत राय और अन्य में।वी.दिल्ली प्रशासन और एएनआर के माध्यम से राज्य।, [1989] 1 एस. सी. सी. 297, अदालत ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि जिस देरी की वह शिकायत कर रहा था, उसके लिए मुख्य रूप से आरोपी स्वयं जिम्मेदार था।

ई.

39. आंध्र प्रदेश राज्य में v.पी. वी. पवित्रन, [1990] 2 एस. सी. सी. 340, इस अदालत ने जांच पूरी करने में अत्यधिक देरी के आधार पर एफ. आई. आर. को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।प्रत्यर्थी एक आई. पी. एस. अधिकारी था जिसके खिलाफ मार्च, 1984 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) के साथ पठित धारा 5 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।उन्हें निलंबित कर दिया गया था लेकिन फिर सितंबर, 1984 में इसे रद्द कर दिया गया और

च

उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया।जुलाई, 1985 में, सरकार ने अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी से कारण दिखाने के लिए कहा कि उसे सेवा से सेवानिवृत्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।प्रत्यर्थी ने उक्त नोटिस को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी जिसे बरकरार रखा गया।इस अदालत में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर गैलरेडी को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया था।इन सबके बाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आई. डी. 1 में आपराधिक कार्यवाही फिर से शुरू की, जिसके बाद प्रतिवादी ने उक्त याचिका को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

*

विलम्ब के आधार पर कार्यवाही।उच्च न्यायालय ने आग्रह किए गए आधार को स्वीकार करते हुए इसे रद्द कर दिया।इस अदालत ने पुष्टि की।बेशक, ऐसा करते समय, इसने इस बात का ध्यान रखा कि एच जांच को पूरा करने में देरी की याचिका की जांच करते समय, अदालत को सभी प्रासंगिक परिस्थितियों और ए. आर. अंतुले बनाम को ध्यान में रखना चाहिए।

आर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]। 365

कि त्वरित जाँच के लिए समान अनुप्रयोग के किसी भी लचीले दिशानिर्देश या कठोर सिद्धांतों ए को तैयार करना संभव नहीं है और न ही जाँच को पूरा करने के लिए सीमा की किसी भी मनमाने अवधि को निर्धारित करना संभव है।संक्षेप में, रघुबीर सिंह के सिद्धांत को दोहराया गया।

!

40. वास्तव में, त्वरित सुनवाई का अधिकार वैधानिक में अंतर्निहित है

इस देश का कानून।उप-दंड संहिता की धारा 309 की धारा 1 और 2।पी. सी. (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 की उप-धारा 1 और 1 ए के अनुरूप,

1898) इस नियम का उदाहरण दीजिए।वे कहते हैंः

1 1

"309. कार्यवाहियों को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति।-- (1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में, कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से आयोजित की जाएगी, और विशेष रूप से, जब गवाहों की परीक्षा सी एक बार शुरू हो जाती है, तो यह दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती है, जब तक कि अदालत को अगले दिन से आगे का स्थगन नहीं मिल जाता है।

कारण दर्ज करने के लिए आवश्यक है।

(2) यदि न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान लेने या विचारण शुरू करने के बाद, प्रारंभ या किसी जांच या विचारण को स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है, तो वह समय-समय पर, दर्ज किए जाने के कारणों से, ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझता है, उस समय के लिए, जो वह उचित समझता है, स्थगित या स्थगित कर सकता है और यदि अभिरक्षा में है तो अभियुक्त को वारंट द्वारा रिमांड पर ले सकता है।ई.

बशर्ते कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के तहत पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेजेगा।

समय।

बशर्ते कि जब गवाह उपस्थित हों, तो बिना जाँच किए कोई विज्ञापन या स्थगन नहीं दिया जाएगा।

उन्हें, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारण को छोड़कर।

बशर्ते कि केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण दिखाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

जी.

प्रावधानों को संहिता की धारा 482 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाता है।बाद वाला प्रावधान मान्यता देता है कि

"न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा" उचित आदेश पारित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।कई मामलों में, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय ने एच को हटाने या बंद करने का निर्देश दिया है।

1 366 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

ऐसी कार्यवाहियाँ जहाँ ऐसी कार्यवाहियाँ न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं या जहाँ न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसी कार्रवाई की माँग की जाती है।हम अब इनमें से कुछ मामलों का उल्लेख कर सकते हैं।

41. मचंदर वी।हैदराबाद राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 524, इस अदालत ने कहा कि यह देखना अदालत का दायित्व है कि कोई भी दोषी व्यक्ति बी बच न जाए, फिर भी यह देखना उसका कर्तव्य है कि न्याय में देरी न हो और आरोपी व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक परेशान न किया जाए।अदालत ने कहा कि तराजू अभियोजन पक्ष और आरोपी के बीच भी होना चाहिए।उस मामले के तथ्यों में, अदालत ने पहले से बिताए गए समय और उस मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के कारण मुकदमे का आदेश देने से इनकार कर दिया।

एस.

वीरभद्र बनाम।रामास्वामी नायकर, [1959]।एस. सी. आर. 1211, यह न्यायालय

इस आधार पर कार्यवाही वापस भेजने से इनकार कर दिया कि पहले से ही पाँच साल की अवधि बीत चुकी है और इस तरह के समय के अंतराल के बाद कार्यवाही जारी रखना मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित नहीं होगा।इसी तरह, छज्जू राम बनाम।राधे शाम, [1971] (पूरक।) एस. सी. आर. 172, अदालत ने तथ्यों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 10 साल की अवधि के बाद फिर से मुकदमे का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

डी मामले की परिस्थितियाँ।यू. पी. राज्य बनामकपिल देव शुक्ला, [1972] 3 एस. सी. सी. 504, हालांकि अदालत ने आरोपी को बरी करने के फैसले को अस्थिर पाया, लेकिन उसने 20 साल के अंतराल के बाद रिमांड का आदेश देने या मुकदमे का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

टी

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कला के अलावा भी।21 इस देश में अदालतें आपराधिक मामलों में अनुचित देरी के बारे में संज्ञान लेती रही हैं और जहां भी ऐसा हुआ है

ई.

:अत्यधिक विलंब या जहां कार्यवाही बहुत लंबे समय से लंबित थी और आगे की किसी भी कार्यवाही को दमनकारी और अनुचित माना जाता था, उन्हें उचित आदेश देकर समाप्त कर दिया जाता था।

42. अब हम कुछ अमेरिकी मामलों पर विचार करेंगे जिन पर दोनों पक्षों एफ ने मजबूत निर्भरता रखी थी।

पहला मामला जिस पर भरोसा किया गया है वह है बार्कर बनाम।विंगो, 33 लॉयर्स एडन।101 वर्ष 1972 में निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ता, बार्कर और एक अन्य व्यक्ति सिलास मैनिंग को जुलाई, 1958 में हुई एक हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।उन्हें सितंबर में संकेत दिया गया था और मुकदमा 21 अक्टूबर, जी 1958 के लिए निर्धारित किया गया था।राज्य के पास अन्य आरोपी मैनिंग के खिलाफ एक मजबूत मामला था और उसका मानना था कि बार्कर को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि मैनिंग उसके खिलाफ गवाही नहीं देता।लेकिन यह तभी संभव था जब मैनिंग को पहले दोषी ठहराया गया था; तभी उससे गवाह के रूप में पूछताछ की जा सकती थी।इसलिए, राज्य ने याचिकाकर्ता के मुकदमे में देरी की और मैनिंग के खिलाफ कार्रवाई की।अंततः, मैनिंग को छह मुकदमों के बाद दिसंबर, 1962 में दोषी ठहराया गया।मैनिंग के खिलाफ कार्यवाही लंबित होने पर, एच अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता ए. आर. एंटूले बनाम के खिलाफ मुकदमे का स्थगन प्राप्त कर रहा था।

आर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

367

(बार्कर) समय-समय पर।10 महीने के बाद, अदालत ने उन्हें ए बांड निष्पादित करने पर रिहा कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्थगन प्राप्त करना जारी रखा।मार्च, 1963 में, मैनिंग की दोषसिद्धि प्राप्त करने के बाद, बार्कर के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी।मुकदमा अक्टूबर, 1963 में आयोजित किया गया था और बार्कर को दोषी ठहराया गया था-उनके त्वरित मुकदमे के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अभियोग को खारिज करने के लिए उनकी याचिका पर फैसला सुनाया गया था।अपीलीय न्यायालय ने पुष्टि की।इसके बाद इस मामले को प्रमाण पत्र पर उच्चतम न्यायालय में लाया गया।अभियुक्त 'बी' का मुख्य तर्क था कि मुकदमा आयोजित करने में पाँच साल की देरी अनुचित रूप से लंबी थी और यह त्वरित मुकदमे के उसके अधिकार का उल्लंघन करता है।अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया।इसने माना कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा ली गई चार साल से अधिक की अवधि बहुत लंबी थी, लेकिन उनका मानना था कि इस कारक को कुछ प्रति-संतुलन कारकों के खिलाफ तौला जाना चाहिए, अर्थात्:(1) याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह न्यूनतम था; (2) वह केवल सी के लिए जेल में था।

10 महीने की अवधि और उसके बाद मुक्त था; और (3) याचिकाकर्ता स्वयं त्वरित सुनवाई नहीं चाहता था।वह भी मैनिंग को बरी करने का जुआ खेल रहा था, जिस मामले में अभियोजन पक्ष ने उस पर मुकदमा नहीं चलाया होगा।

43. न्यायालय की कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा।

डी.

त्वरित विचारण के अधिकार के संबंध में।हम कुछ मामलों में इस मामले का उल्लेख कर रहे हैं।

इस कारण का विवरण दें कि इस निर्णय का न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों में पालन किया गया है, बल्कि प्रिवी काउंसिल द्वारा भी अनुमोदित किया गया है, जैसा कि हम वर्तमान में इंगित करेंगे।न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को उनके अपने शब्दों में निर्धारित किया जा सकता हैः

ई.

" त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त की सुरक्षा के लिए संविधान में निहित किसी भी अन्य अधिकार से सामान्य रूप से अलग है।इस सामान्य चिंता के अलावा कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के साथ सभ्य और निष्पक्ष प्रक्रियाओं के अनुसार व्यवहार किया जाए, एक त्वरित मुकदमा प्रदान करने में एक सामाजिक हित है जो अभियुक्त के हितों से अलग और कभी-कभी विपक्ष में भी मौजूद है।च

त्वरित सुनवाई के अधिकार और अभियुक्त के अन्य संवैधानिक अधिकारों के बीच दूसरा अंतर यह है कि अधिकार से वंचित रहना अभियुक्त के लाभ के लिए काम कर सकता है।देरी एक असामान्य रक्षा रणनीति नहीं है।जैसे-जैसे अपराध करने और मुकदमे के बीच का समय बढ़ता है, गवाह अनुपलब्ध हो सकते हैं या उनकी यादें फीकी पड़ सकती हैं।

जी.

त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित होने से अभियुक्त की अपना बचाव करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। त्वरित सुनवाई का अधिकार है

अन्य प्रक्रियात्मक अधिकारों की तुलना में अधिक अस्पष्ट अवधारणा।उदाहरण के लिए, यह सटीक रूप से निर्धारित करना असंभव है कि अधिकार कब दिया गया है।

मना कर दिया।हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि किसी प्रणाली में कितना समय बहुत लंबा होता है।

जहाँ न्याय त्वरित लेकिन जानबूझकर माना जाता है।एक कॉन्स के रूप में

क.

उदाहरण के लिए, आपराधिक प्रक्रिया में कोई निश्चित बिंदु नहीं है।जब राज्य प्रतिवादी को त्वरित सुनवाई के अधिकार का प्रयोग करने या उसे माफ करने का विकल्प दे सकता है।

अधिकार की अनाकार गुणवत्ता भी अभियोग को खारिज करने के असंतोषजनक गंभीर उपचार की ओर ले जाती है जब अधिकार के पास है

वंचित कर दिया गया।यह वास्तव में एक गंभीर परिणाम है क्योंकि इसका मतलब है कि एक प्रतिवादी जो एक गंभीर अपराध का दोषी हो सकता है, बिना मुकदमा चलाए रिहा हो जाएगा।इस तरह का उपचार एक बहिष्करण नियम या एक नए परीक्षण के लिए उलटने की तुलना में अधिक गंभीर है, लेकिन यह एकमात्र संभावित उपाय है।

इसलिए हम इस नियम को अस्वीकार करते हैं कि एक प्रतिवादी जो त्वरित मुकदमे की मांग करने में विफल रहता है, हमेशा के लिए अपने अधिकार को माफ कर देता है।ऐसा नहीं है।

तथापि, इसका अर्थ यह है कि प्रतिवादी के पास अपने अधिकार का दावा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।हम सोचते हैं कि बेहतर नियम यह है कि प्रतिवादी का दावा या त्वरित मुकदमे के अपने अधिकार का दावा करने में विफलता उन कारकों में से एक है जो एल

डी.

अधिकार से वंचित होने की जांच में विचार किया जाना

हम जिस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं वह एक संतुलन परीक्षण है, जिसमें आचरण

अभियोजन पक्ष और प्रतिवादी दोनों का वजन किया जाता है।

ई.

एक संतुलन परीक्षण अनिवार्य रूप से अदालतों को तदर्थ आधार पर त्वरित परीक्षण मामलों तक पहुंचने के लिए मजबूर करता है। हम कुछ कारकों की पहचान करने से थोड़ा अधिक कर सकते हैं जिनका अदालतों को यह निर्धारित करने में आकलन करना चाहिए कि क्या किसी विशेष प्रतिवादी को उसके अधिकार से वंचित किया गया है।हालाँकि कुछ लोग उन्हें अलग-अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, हम ऐसे चार कारकों की पहचान करते हैंःदेरी की अवधि, देरी का कारण,

च

प्रतिवादी का अपने अधिकार का दावा, और प्रतिवादी के प्रति पूर्वाग्रह

11 -

देरी की अवधि कुछ हद तक एक ट्रिगरिंग तंत्र है।जब तक कुछ देरी नहीं होती है जो अनुमानित रूप से प्रतिकूल है, तब तक अन्य कारकों की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है जो

जी.

संतुलन

ऊपर पहचाने गए चार कारक संबंधित कारक हैं और इन पर ऐसी अन्य परिस्थितियों के साथ विचार किया जाना चाहिए जो हो सके।

(

प्रासंगिक बनें

अदालतों को अभी भी एक कठिन और

संवेदनशील संतुलन प्रक्रिया।लेकिन, क्योंकि हम एक से निपट रहे हैं

एच.

[1

369

ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

(

अभियुक्त का मौलिक अधिकार, इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए

पूर्ण मान्यता के साथ कि त्वरित मुकदमे में अभियुक्त की रुचि है

संविधान में विशेष रूप से पुष्टि की गई है।

अल।

44. स्ट्रंक वी में।संयुक्त राज्य अमेरिका, 37 लॉयर्स एडन।256 यह अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक आरोपों की त्वरित जांच का अभियुक्त का अधिकार मौलिक है और आरोप लगाने वाले प्राधिकारी का कर्तव्य त्वरित सुनवाई प्रदान करना है।1 बी में यह देखा गया कि अभियुक्त या अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं या सुविधा की बहुत कम प्रासंगिकता है और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियोजक के दायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।इस मामले में विचार किया गया मुख्य प्रश्न यह था कि क्या उक्त गारंटी के उल्लंघन में आरोपों को खारिज करना शामिल है।यह आयोजित किया गया था

1

- कि आरोपों को खारिज करना ही एकमात्र संभावित उपाय है जहां त्वरित मुकदमे से इनकार कर दिया गया है।वास्तव में, इस मामले में, अपील अदालत की यह भी राय थी कि सी अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार किया गया था, लेकिन उसने आरोपों को रद्द नहीं किया, बल्कि केवल निर्देश दिया कि अभियुक्त को दी गई सजा को असंवैधानिक देरी की अवधि से कम किया जाना चाहिए।(जिला अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद मामले को अपीलीय अदालत में ले जाया गया)।45. बेल वी में।अभियोजन निदेशक, जमैका, [1985] 2 ए. ई. आर. 585, प्रिवी काउंसिल ने बार्कर में प्रतिपादित सिद्धांतों की स्पष्ट रूप से पुष्टि की

निम्नलिखित शब्दः

" उनके प्रभुत्त्व स्पष्ट रूप से विस्तारित और व्यापक रूप से चर्चा किए गए चार कारकों की प्रासंगिकता और महत्व को स्वीकार करते हैं।

}

बार्कर वी.विंगो।उनके अधिपति किसी भी संविधान के लिए समान या समान मानदंडों को लागू करने की देसी क्षमता को भी स्वीकार करते हैं।

1

लिखित या अलिखित, जो किसी अभियुक्त को आपराधिक कार्यवाही में देरी करके उत्पीड़न से बचाता है।तथापि, प्रत्येक कारक के साथ जोड़ा जाने वाला भार क्षेत्राधिकार से लेकर क्षेत्राधिकार तक भिन्न होना चाहिए।

केस टू केस "।

च

इस मामले में, प्रिवी काउंसिल ने एक विशेष प्रणाली में निहित देरी पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।प्रिवी काउंसिल जमैका के एक मामले से निपट रही थी।जमैका के अपील न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस देश में प्राप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 32 महीने की देरी को त्वरित मुकदमे के लिए एक आरोपी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। प्रिवी काउंसिल ने देखा कि जमैका की अदालत की यह राय, जो

उसे उस देश की स्थितियों से परिचित माना जाना चाहिए, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।लेकिन, चूंकि यह पुनः विचारण का मामला था, प्रिवी काउंसिल ने माना कि उक्त विलंब को उक्त अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए।बोर्ड

इस बात पर जोर दिया गया कि पुनः सुनवाई अधिक तेजी से की जानी चाहिए और पुनः सुनवाई के मामले में जिस देरी को नजरअंदाज किया जा सकता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।एच.

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

जी 370

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. संयुक्त राज्य अमेरिका में वी।हॉक 88 लॉयर्स एंड।2 और 640, अभियुक्त थे

क.

नवंबर, 1975 में अवैध रूप से आग्नेयास्त्र और विस्फोटक रखने के लिए संकेत दिया गया था।अभियुक्तों ने अपने कथित सबूतों को छिपाने का प्रस्ताव रखा

डायनामाइट का कब्जा इस आधार पर कि डायनामाइट को राज्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था।जब मई में मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो अभियोजन पक्ष ने तैयार नहीं होने की सूचना दी।जिला अदालत ने पूर्वाग्रह के साथ अभियोग बी को खारिज कर दिया।अगले सात वर्षों के दौरान, रिमांड के आदेशों के बाद अपील न्यायालय के साथ-साथ जिला अदालत में भी कई कार्यवाहियां हुईं।46 महीने की अवधि के दौरान, यानी अभियोग को खारिज करने की तारीख से, अपील अदालत के आदेश के बाद अभियोग की पुनः स्थापना तक, प्रतिवादियों को बिना शर्त रिहा कर दिया गया था।अपील न्यायालय से रिमांड के बाद, जिला न्यायालय ने मई, 1983 में अभियुक्त के विशेष मुकदमे के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अभियोग को खारिज कर दिया।अंततः इस मामले को उच्चतम न्यायालय में लाया गया, जहां अधिकांश न्यायाधीशों (5ः4) ने यह अभिनिर्धारित किया कि जिस समय के दौरान प्रतिवादी न तो अभियोग के अधीन थे और न ही किसी आधिकारिक प्रतिबंध के अधीन थे और जहां अंतर्वर्ती अपीलों के कारण देरी हुई थी, उसे देरी के रूप में नहीं गिना जा सकता है और उस आधार पर अभियुक्त को किसी भी राहत का अधिकार नहीं है।हालाँकि, अल्पमत ने माना कि हालाँकि प्रतिवादी के खिलाफ अभियोग खारिज कर दिया गया था और उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया था, उनका मामला निचली अदालत के पास बना रहा और उनके मामले में अपील के लिए लिया गया समय स्पष्ट रूप से अनुचित था।उक्त देरी के लिए अभियोजन पक्ष को नुकसान उठाना चाहिए न कि आरोपी को।हम इस मामले के तर्क को किसी भी विस्तार से संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंकि यह सभी मामलों में बार्कर सिद्धांतों की पुष्टि करने के अलावा मुख्य रूप से प्रश्न से संबंधित है।

ई.

क्या अंतर्वर्ती अपीलों पर मुकदमा चलाने में लगने वाले समय को देरी के रूप में गिना जाना चाहिए या नहीं, विशेष रूप से जहां अभियुक्तों को उस अवधि के दौरान बिना शर्त रिहा किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा, अमेरिका में कानून के कई प्रोफेसरों द्वारा कुछ अन्य अमेरिकी मामले और लेख हमारे ध्यान में लाए गए हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं

च

उन सभी विचारों के साथ इस निर्णय को बोझ बनाना चाहते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश या तो बार्कर, हॉक और अन्य मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं।47. इस स्तर पर, हम माधेश्वर सिंह के तथ्यों और सिद्धांतों से निपटना उचित समझते हैं।वी.बिहार राज्य, (ए. आई. आर. 1986 जी. पैना 324) (पूर्ण पीठ) जो निर्णय बिहार राज्य द्वारा 1987 की आपराधिक अपील संख्या 126 का विषय है।वास्तव में, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्तों के विद्वान वकील ने इस पर दृढ़ता से भरोसा किया।पूर्ण पीठ को पाँच प्रश्न भेजे गए थे, अर्थात्:

"1. क्या त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार पूर्ववर्ती जनादेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है

एच.

केवल मृत्युदंड के अपराधों के लिए या सामान्य रूप से सभी अपराधों के लिए आकर्षित है?

371

ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

2. क्या त्वरित सुनवाई का उपरोक्त अधिकार केवल न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होता है या इसके दायरे में पूर्ववर्ती पुलिस जांच भी शामिल है?

3. क्या त्वरित सुनवाई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अक्षर और भावना दोनों द्वारा समान रूप से अनिवार्य है?

पी.

4. चाहे रामदारास अहीर के मामले (1985 सी. आर. आई. एल. जे. 584) (पट) (ऊपर) और मकसूदन सिंह के मामले (ए. आई. आर. 1986 पट) में अनुपात।38 (एफ. बी.) (उपर्युक्त) सभी अपराधों पर समान रूप से लागू होते हैं और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या कार्यवाही एक परीक्षण है या बरी होने के खिलाफ अपील है?

एस.

5. क्या त्वरित सार्वजनिक मुकदमे के अधिकार को ठोस बनाने के लिए एक बाहरी सीमा की कल्पना पूर्ववर्ती के सिद्धांत द्वारा की गई है?

मामले के तथ्य असामान्य हैं-बिहार राज्य में इतने असामान्य नहीं हो सकते हैं।उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता, माधेश्वरधारी सिंह प्रथम श्रेणी के सरकार अधिकारी थे।वर्ष 1964-65 के दौरान, उन्हें केंद्रीय कुक्कुट फार्म, पटना में सहायक निदेशक के रूप में तैनात किया गया था।सत्यनारायण शर्मा पर, स्टोर कीपर उक्त खेत में उनके अधीनस्थ थे।उनके उत्तराधिकारी द्वारा की गई एक लिखित शिकायत के आधार पर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थी

20 नवंबर, 1966 को आई. पी. सी. की धारा 467,409 और 120 बी के तहत सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।याचिकाकर्ता को अभियुक्त ई के रूप में नामित नहीं किया गया था

उस रिपोर्ट में।हालाँकि, उसमें लगाए गए आरोपों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भी संदेह का बादल फैला दिया।पुलिस द्वारा जाँच जारी रही और अंततः 29 सितंबर, 1975 को याचिकाकर्ता को भी उक्त मामले में आरोपी बना दिया गया।याचिकाकर्ता के अनुसार, यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया था और उनके करियर और पदोन्नति की संभावनाओं को खतरे में डालने के लिए किया गया था।चाहे जो भी हो, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें एफ.

क.

20 अप्रैल, 1975 को अस्थायी जमानत, जिसकी बाद में पुष्टि की गई।30 जनवरी, 1976 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।इसके बाद कार्यवाही बहुत धीमी गति से आगे बढ़ी।जुलाई, 1977 में आरोप तय किए गए।अदालत के निर्देशों के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने गवाहों से त्वरित उत्तराधिकार में नहीं बल्कि ड्रिबलेट में पूछताछ की।यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष अपने आदेशों पर ध्यान नहीं दे रहा था और न ही सबूत पेश कर रहा था, विद्वान मजिस्ट्रेट ने अप्रैल, 1984 में गद्य-2 के मुकदमे को बंद कर दिया।यह इंगित करना आवश्यक है कि जुलाई, 1977 (जब उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे) और अप्रैल, 1984 (जब विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्ष का मामला बंद कर दिया था) के बीच उद्धृत 40 गवाहों में से केवल 9 गवाहों से ही पूछताछ की गई थी।निचली अदालत के अपने मामले को बंद करने के आदेश से नाराज अभियोजन पक्ष ने एक संशोधन को प्राथमिकता दी, जिसमें मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष को अवसर देने का निर्देश दिया गया।फिर भी, अभियोजन पक्ष ने एच 372 का लाभ नहीं उठाया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवसर का एक।विद्वान मजिस्ट्रेट ने सितंबर, 1984 में एक बार फिर अभियोजन पक्ष के मामले को बंद कर दिया।राज्य इस आदेश के खिलाफ विद्वान सत्र न्यायाधीश के पास गया और फिर से विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को अभियोजक को गवाहों से पूछताछ करने का अवसर देने का निर्देश दिया।जनवरी 1985 में, केवल एक गवाह से पूछताछ की गई और उसके बाद किसी से पूछताछ नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष का मामला 1 मई 1985 को फिर से बंद कर दिया गया।इस स्तर पर, बी अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई कि उस पर मुकदमा चलाने के लिए कोई वैध मंजूरी नहीं थी।मंजूरी के आदेश की एक प्रति पेश करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कई स्थगन प्राप्त किए लेकिन इसे पेश नहीं किया।अंततः, 1 अक्टूबर, 1985 को याचिकाकर्ता ने विद्वत मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि जांच और मुकदमे में लगभग 20 साल बीतने से त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और उस आधार पर सी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

48. संधवालिया, सी. जे.।, की समीक्षा पर आयोजित पूर्ण रेन्च के लिए बोलते हुए

इस न्यायालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई निर्णय; त्वरित मुकदमे का अधिकार कला में निहित है और कला से प्रवाहित होता है।21. विद्वान मुख्य न्यायाधीश डी ने निम्नलिखित चार सिद्धांतों को अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होने के रूप में कहा, अर्थात्।,

"1. कि, अब पूर्ववर्ती अधिदेश द्वारा सभी आपराधिक अभियोजनों में त्वरित सार्वजनिक मुकदमे के मूल मानव अधिकार को स्पष्ट रूप से लिखा गया है जैसे कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक अधिकार में कलम और स्याही के साथ लिखा गया है।

आई.

ई.

इसके अलावा, यह अधिकार अमेरिकी संविधान में छठे संशोधन द्वारा अंतःस्थापित व्यक्त संवैधानिक गारंटी के साथ सामग्री में समान है।

2. कि उस संविधान के छठे संशोधन पर अमेरिकी उदाहरण समान रूप से आकर्षित और लागू होंगे

च

हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के इस पहलू पर भी गौर करें।3. कि एक बार त्वरित सुनवाई और अनुच्छेद 21 के तहत एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अधिकार की संवैधानिक गारंटी है

जे.

उल्लङ्घन किया जाता है, तब अभियुक्त बिना शर्त रिहाई का हकदार होता है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप

जी.

जमीन।

4. कि दस वर्ष या उससे अधिक की कठोर और अत्यधिक लंबी देरी, जो किसी भी तरह से अभियुक्त के चूक से उत्पन्न नहीं होती है (या अन्यथा किसी असाधारण और असाधारण कारणों से नहीं होती है), एक पूंजी पर एक स्पष्ट बरी होने के उलट होने के संदर्भ में।

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.] 373

आरोप स्वयं अभियुक्त के लिए प्रतिकूल होगा और अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई की संवैधानिक गारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करेगा।

पूर्ण पीठ के अन्य निष्कर्ष निम्नलिखित प्रभाव वाले हैंः1. त्वरित विचारण का अधिकार न केवल बड़े अपराधों पर बल्कि बी छोटे अपराधों पर भी लागू होता है।

2. यह न केवल न्यायालय की कार्यवाही बल्कि पूर्ववर्ती पुलिस जाँच को भी अपने दायरे में लेता है।

एफ.

3. दंड प्रक्रिया संहिता और बिहार सी पुलिस नियमावली के प्रावधान न केवल त्वरित सार्वजनिक मुकदमे की भावना को मूर्त रूप देते हैं, बल्कि वास्तव में, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर त्वरित और त्वरित निपटान को अनिवार्य करने वाले स्पष्ट प्रावधानों द्वारा इसका प्रतीक हैं।अनुच्छेद 21 और संहिता के प्रावधानों के बीच कोई टकराव नहीं है।

इस निर्णय में अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत डी से संबंधित है

सवाल यह है कि क्या उक्त अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।इस न्यायालय के कई फैसलों की विस्तृत जांच के बाद, जिनमें शामिल हैं -

शीला बार्से और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की विद्वान न्यायाधीश निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचीः

ई.

त्वरित सार्वजनिक मुकदमे के अधिकार को ठोस बनाने के लिए एक बाहरी सीमा की परिकल्पना सिद्धांत और पूर्ववर्ती दोनों द्वारा की गई है।यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि गंभीर अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए जांच और मूल मुकदमे में सात साल या उससे अधिक की कठोर और अत्यधिक लंबी देरी (जो अभियुक्त के चूक से उत्पन्न नहीं होती है या अन्यथा किसी असाधारण या असाधारण कारण से नहीं होती है) अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सार्वजनिक मुकदमे की संवैधानिक गारंटी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करती है।

च

उन्होंने आगे कहाः

" सावधानी का एक तीखा संकेत दिया जाना चाहिए।उपरोक्त निष्कर्ष 1 जी को गलत नहीं समझा जाना चाहिए या इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि सात साल से कम की देरी किसी भी मामले में पूर्वाग्रह के बराबर नहीं होगी।अल।

वास्तव में, जो निर्धारित करने की मांग की गई है वह चरम बाहरी सीमा है

यू.

जहां अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह का अनुमान लगाया जाना चाहिए और संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाएगा।वास्तव में, मुझे एच 374 की वर्तनी लिखने में कुछ हिचकिचाहट हो रही है।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त बाहरी समय सीमा जो, शायद, सख्ती के पक्ष में गलती करती है।लेकिन चूंकि हम बाध्यकारी मिसाल का पालन कर रहे हैं, इसलिए इसे बिना शर्त स्वीकार किया जाना चाहिए।न ही यह निर्धारित करने की कोशिश की गई है कि सात साल से कम की अवधि में कोई अभियुक्त व्यक्ति उन परिस्थितियों को स्थापित करने में सक्षम नहीं होगा, जो पेटेंट पूर्वाग्रह की ओर इशारा करते हैं जो उसे अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सार्वजनिक मुकदमे की गारंटी का आह्वान करने का अधिकार दे सकते हैं।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने तब विकसित सिद्धांतों के आलोक में अपने समक्ष मामले के तथ्यों की जांच की और कहा कि यह एक स्पष्ट मामला है जहां याचिकाकर्ता के त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।उन्होंने पाया कि याचिकाकर्ता अवरोधक रणनीति का दोषी नहीं था और देरी पूरी तरह से अभियोजन पक्ष द्वारा की गई थी।तदनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच और मुकदमे को रद्द कर दिया गया।राज्य बनाम में आयोजित उसी विद्वान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अन्य पूर्ण पीठ।मकसूदन सिंह, ए. आई. आर. 1986 पटना 38 ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों के मामले में, अभियोजन की चूक के कारण पूरी तरह से 10 साल या उससे अधिक की देरी को अभियुक्त के लिए प्रतिकूल माना जाना चाहिए।

49. अनुच्छेद 21 घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।इस देश में मुख्य प्रक्रियात्मक कानून दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 है।कई अन्य अधिनियमों में भी कई प्रक्रियात्मक प्रावधान हैं।मेनका गांधी के बाद इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि 'कानून' (जिसे समझना होगा)

इस अर्थ में कि अनुच्छेद 21 में संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड (3) (ए) में परिभाषित अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 19 और 14 में निहित तर्कसंगतता और निष्पक्षता की कसौटी का जवाब देना होगा।दूसरे शब्दों में, इस तरह के कानून को एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करनी चाहिए जो निष्पक्ष, उचित और न्यायपूर्ण हो।केवल तभी यह अनुच्छेद 21 के आदेश के अनुरूप होगा।वास्तव में, जहां भी आवश्यक हो, ऐसी निष्पक्षता को ऐसे कानून में पढ़ा जाना चाहिए।अब, क्या यह कहा जा सकता है कि एक कानून जो एक आपराधिक मामले की उचित रूप से त्वरित जांच, परीक्षण और निष्कर्ष का प्रावधान नहीं करता है, वह निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित है?यह दोनों अभियुक्त के हित में है।

साथ ही समाज कि एक आपराधिक मामला जल्द ही समाप्त हो जाता है।यदि अभियुक्त है।उसे दोषी घोषित किया जाना चाहिए। सामाजिक हित दोषी को दंडित करने और निर्दोष को दोषमुक्त करने में निहित है, लेकिन यह निर्धारण (अपराध या निर्दोषता का) उचित प्रेषण के साथ किया जाना चाहिए-मामले के सभी परिवेशक स्थितियों में उचित।चूँकि यह अभियुक्त है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है और

यदि वह व्यक्ति भी है जिसका जीवन और/या स्वतंत्रता खतरे में है, तो यह कहना उचित होगा कि उसे तेजी से मुकदमा चलाने का अधिकार है।तदनुसार, इस अधिकार का सम्मान करना और सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।यह कहने पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अपराध का आरोपी होने का तथ्य ही चिंता का विषय है।यह अपने सहयोगियों और समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और स्थिति को प्रभावित करता है।

यह एक कारण है ए. आर. एंटूले बनाम।आर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

375

1 चिंता और खर्च के लिए।अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो यह अधिक होता है।यदि यह एक गंभीर अपराध है, तो वह व्यक्ति अपना जीवन, स्वतंत्रता, करियर और वह सब कुछ खो सकता है जिसे वह संजोता है।+50. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान सुसंगत हैं और वास्तव में इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं।वे शीघ्र जाँच और त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई का प्रावधान करते हैं।विद्वान महान्यायवादी का यह कहना सही है कि यदि केवल संहिता के प्रावधानों का उनके अक्षर और भावना में पालन किया जाता है, तो बी में किसी भी शिकायत के लिए बहुत कम जगह होगी।हालांकि, तथ्य अभी भी-अप्रिय है।

(

क्योंकि यह है कि कई मामलों में, इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिक सम्मान किया जाता है।चाहे जो भी हो, यह कहना पर्याप्त है कि अनुच्छेद 21 से त्वरित सुनवाई की संवैधानिक गारंटी संहिता के प्रावधानों में उचित रूप से परिलक्षित होती है।

एस.

51. लेकिन फिर त्वरित परीक्षण या उक्त धारणा को व्यक्त करने वाली अन्य अभिव्यक्तियाँ अनिवार्य रूप से प्रकृति में सापेक्ष हैं। कोई पूछ सकता है-तेज़ का मतलब है, कितना तेज़?देरी कितनी लंबी होती है?हमें नहीं लगता कि आपराधिक कार्यवाही के समापन के लिए कोई समय सारिणी निर्धारित करना संभव है।प्रकृति.

अपराध, अभियुक्तों की संख्या, गवाहों की संख्या, विशेष न्यायालय में कार्य-भार, संचार के साधन और कई अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।उदाहरण के लिए, उसी मामले को लें जिसमें रंजन द्विवेदी (1987 की रिट याचिका संख्या 268 में याचिकाकर्ता) आरोपी हैं।151 अभियोजन पक्ष द्वारा पाँच वर्षों की अवधि में गवाहों से पूछताछ की गई है।कुछ गवाहों की जाँच 100 से अधिक टाइप किए गए पृष्ठों में होती है।अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए वास्तविक साक्ष्य में हम ई हैं

बताया, 4000 पृष्ठ।भले ही, सप्ताह के पांच दिन और सप्ताह दर सप्ताह मामले को जारी रखने का प्रस्ताव था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह संभव नहीं था।, वकीलक अनुपलब्धता, अभियुक्तक अनुपलब्धता, अंतर्वर्ती कार्यवाही आ अन्य प्रणालीगत विलम्ब। एक हत्या का मामला एक साधारण मामला हो सकता है जिसमें एक दर्जन गवाह शामिल हो सकते हैं जिन्हें एक सप्ताह में समाप्त किया जा सकता है जबकि एक अन्य मामले में बड़ी संख्या में गवाह शामिल हो सकते हैं, और इसमें अलग-अलग एफ हो सकता है।

सप्ताह।अपनी प्रकृति के कुछ अपराध जैसे कि साजिश के मामले, गबन, गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी, राजद्रोह, लोक सेवकों द्वारा आनुपातिक संपत्ति का अधिग्रहण, उच्च लोक सेवकों और उच्च लोक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और मुकदमे में अधिक समय लगता है।फिर, प्रत्येक न्यायालय, जिले, क्षेत्र और राज्य में काम का बोझ अलग-अलग होता है।यह तथ्य हमारे हाथों उदाहरण के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है।कई स्थानों पर जी आवश्यक संख्या में अदालतें उपलब्ध नहीं हैं।कुछ स्थानों पर, बार के सदस्यों द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़तालें कार्य-अनुसूची में हस्तक्षेप करती हैं।संक्षेप में, चीजों की प्रकृति और वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है कि एक समय सीमा तय की जाए जिससे आगे आपराधिक कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी रेखा खींचने से इनकार कर दिया है।अपील के तहत पटना एफ. बी. के निर्णय को छोड़कर, एच. 376 में किसी भी उच्च न्यायालय का कोई अन्य निर्णय नहीं

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह का दृष्टिकोण रखने वाले इस देश को हमारे संज्ञान में लाया गया है।न ही, हमारी जानकारी के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में।जहाँ कहीं भी त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत की जाती है, वहाँ अदालत को ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों

सहित मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करना होता है और इस निर्णय पर पहुंचना होता है कि क्या वास्तव में कार्यवाही अन्यायपूर्ण रूप से लंबी अवधि से लंबित है।कई मामलों में, आरोपी स्वयं देरी के लिए जिम्मेदार हो सकता है।ऐसे मामलों में बी को अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।कुछ मामलों में, देरी हो सकती है जिसके लिए न तो अभियोजन पक्ष और न ही आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, बल्कि व्यवस्था को ही दोषी ठहराया जा सकता है।मोटे तौर पर, ऐसे दिनों को भी अनुचित नहीं माना जा सकता है।बेशक, अगर यह एक मामूली अपराध है-एक आर्थिक अपराध नहीं होने के कारण-और देरी बहुत लंबी है, आरोपी के कारण नहीं, तो अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं।प्रत्येक मामले को इसके बाद प्रतिपादित सी सिद्धांतों के संबंध में अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।उपरोक्त सभी कारणों से, हमारी राय है कि सभी आपराधिक कार्यवाही के समापन के लिए एक बाहरी समय सीमा निकालना या निर्धारित करना न तो उचित है और न ही संभव है।त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है।हम भी संतुष्ट नहीं हैं कि

*

ऐसी बाहरी सीमा के बिना, अधिकार भ्रामक हो जाता है।

डी.

52. हम आगे उस पर विचार कर सकते हैं, जिसे 'मांग' नियम कहा जाता है।द.

तर्क यह है कि एक अभियुक्त जो त्वरित सुनवाई की मांग नहीं करता है, जो खड़ा रहता है और देरी में सहमत होता है, वह अवधि समाप्त होने के बाद अचानक वापस नहीं आ सकता है और त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है।इस तर्क को स्वीकार करना भी संभव नहीं है।अभियुक्त मुकदमा नहीं चलाता है।

स्वयं।राज्य या शिकायतकर्ता उस पर मुकदमा चलाता है।इस प्रकार, ई राज्य या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, का दायित्व है कि वह उचित शीघ्रता के साथ मामले को आगे बढ़ाए।विशेष रूप से, इस देश में, जहां अधिकांश अभियुक्त समाज के गरीब कमजोर वर्गों से आते हैं, जो कानून के तरीकों में पारंगत नहीं हैं, जहां उन्हें अक्सर सक्षम कानूनी सलाह नहीं मिलती है, उक्त नियम का अनुप्रयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य है।बेशक, किसी मामले में, यदि कोई आरोपी त्वरित सुनवाई की मांग करता है और फिर भी उसे एक नहीं दिया जाता है, तो हो सकता है

च

उसके पक्ष में प्रासंगिक कारक।लेकिन हम किसी अभियुक्त को त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाने से इस आधार पर वंचित नहीं कर सकते कि उसने त्वरित सुनवाई की मांग या आग्रह नहीं किया था।

53. एक और सवाल जो हमारे सामने गंभीरता से उठाया गया है, वह त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है।के लिए वकील

जी.

अभियुक्त ने शीला बारसे और स्ट्रंक में टिप्पणियों के आधार पर तर्क दिया कि एकमात्र परिणाम आरोपों को रद्द करना और/या दोषसिद्धि है, जैसा भी मामला हो।आम तौर पर ऐसा हो सकता है।लेकिन हमें नहीं लगता कि यह एकमात्र आदेश है जो अदालत के लिए खुला है।किसी मामले में, तथ्य-अपराध की प्रकृति सहित-ऐसे हो सकते हैं कि आरोपों को रद्द करना न्याय के हित में न हो। आखिरकार, एच प्रत्येक अपराध-विशेष रूप से आर्थिक अपराध, जो लोक अधिकारियों ए. आर. अंतुले बनाम से संबंधित हैं।

आर. एस. नायक (रेड्डी, जे.)

377

और भोजन में मिलावट समाज के खिलाफ अपराध है।यह वास्तव में समाज ए राज्य है जो अपराधी पर मुकदमा चलाता है।हम इस संबंध में चंपालाल पुंजाजी शाह में इस अदालत की टिप्पणियों को याद कर सकते हैं।ऐसे मामलों में, जहां आरोपों/दोषसिद्धि को रद्द करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है, अदालत के लिए ऐसे उचित आदेश पारित करने के लिए खुला होगा जो न्यायसंगत माने जा सकते हैं।

मामले की परिस्थितियाँ।उदाहरण के लिए, ऐसे आदेश मुकदमे के अभियान और एक विशेष निर्धारित बी अवधि के भीतर इसके निष्कर्ष के लिए आदेश का रूप ले सकते हैं, सजा में कमी जहां मामला मुकदमे और दोषसिद्धि के समापन के बाद आता है, और इसी तरह।

54. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं, जो दिशानिर्देशों के रूप में काम करते हैं।हमें पहले से सचेत रहना चाहिए कि ये प्रस्ताव संपूर्ण नहीं हैं।सभी स्थितियों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है।न ही सी. को कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित करना संभव है।ये प्रस्ताव इस प्रकार हैंः

1. संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया

संविधान अभियुक्त पर तेजी से मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।त्वरित सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का अधिकार है।यह तथ्य कि त्वरित मुकदमा भी जनहित में है या यह सामाजिक हित की भी सेवा करता है, इसे अभियुक्त का अधिकार नहीं बनाता है।यह सभी संबंधित लोगों के हित में है कि अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण जल्द से जल्द किया जाए।

2. अनुच्छेद 21 से आने वाले त्वरित सुनवाई के अधिकार में सभी ई शामिल हैं।

चरण, अर्थात् जांच, जांच, परीक्षण, अपील, संशोधन और पुनः परीक्षण का चरण।इस तरह, इस अदालत ने इस अधिकार को समझ लिया है और प्रतिबंधित दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है।

3. अभियुक्त के दृष्टिकोण से त्वरित सुनवाई के अधिकार में अंतर्निहित चिंताएँ हैंः

च

(क) रिमांड और पूर्व-दोषसिद्धि निरोध की अवधि यथासंभव कम होनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, अभियुक्त को नहीं होना चाहिए

उसकी दोषसिद्धि से पहले अनावश्यक या अनुचित रूप से लंबे कारावास के अधीन;

जी.

(ख) अनावश्यक रूप से लंबी जांच, जांच या मुकदमे के परिणामस्वरूप उसके व्यवसाय और शांति के लिए चिंता, चिंता, खर्च और अशांति न्यूनतम होनी चाहिए; और

(ग) अनुचित विलम्ब के परिणामस्वरूप अभियुक्त की अपना बचाव करने की क्षमता में हानि हो सकती है, चाहे वह मृत्यु के कारण हो, गायब हो जाए या गवाहों की अनुपलब्धता हो या अन्यथा।

378 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।[1991] एसयूपीपी।3 एस. सी. आर. ए 4.उसी तरह।इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आमतौर पर आरोपी ही कार्यवाही में देरी करने में रुचि रखता है।जैसा कि अक्सर बताया जाता है, "देरी एक ज्ञात रक्षा रणनीति है"।चूँकि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, इसलिए देरी आमतौर पर अभियोजन पक्ष को पूर्वाग्रहित करती है।गवाहों की अनुपलब्धता, समय के साथ साक्ष्य का गायब होना वास्तव में अभियोजन पक्ष के हितों के खिलाफ काम करता है।बेशक, बी मामले हो सकते हैं जहां अभियोजन पक्ष, किसी भी कारण से, कार्यवाही में देरी करता है।इसलिए, प्रत्येक मामले में, जहां त्वरित सुनवाई के अधिकार का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है, पहला सवाल रखा जाना चाहिए और जवाब दिया जाना चाहिए-देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?अपने अधिकारों और हितों को सही साबित करने के लिए सद्भावना से किसी भी पक्ष द्वारा की गई कार्यवाही, जैसा कि वे समझते हैं, को देरी की रणनीति के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसी कार्यवाही को आगे बढ़ाने में लगने वाले समय को देरी के रूप में गिना जा सकता है।ग. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि केवल गणना के दिन में देरी करने के लिए की गई तुच्छ कार्यवाही या कार्यवाही को सद्भावना से की गई कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है।केवल यह तथ्य कि एक आवेदन/याचिका स्वीकार की जाती है और एक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन का आदेश अपने आप में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कार्यवाही तुच्छ नहीं है।बहुत बार ये पूर्व-पक्षीय प्रतिनिधित्व पर प्राप्त होते हैं। डी 5।यह निर्धारित करते समय कि क्या अनुचित विलम्ब हुआ है (जिसके परिणामस्वरूप त्वरित विचारण के अधिकार का उल्लंघन हुआ है) अपराध की प्रकृति, अभियुक्तों और गवाहों की संख्या, संबंधित न्यायालय के कार्य-भार, प्रचलित स्थानीय स्थितियों और इसी तरह, जिसे प्रणालीगत विलम्ब कहा जाता है, सहित सभी परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।यह सच है कि यह राज्य का दायित्व है कि वह त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करे और राज्य में न्यायपालिका भी शामिल है, लेकिन एक यथार्थवादी और

ई.

ऐसे मामलों में पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।6. प्रत्येक विलम्ब आवश्यक रूप से अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखता है।कुछ देरी वास्तव में उसके लाभ के लिए काम कर सकती है।जैसा कि देखा गया है

पॉवेल, जे. बार्कर में "यह नहीं कहा जा सकता है कि एक ऐसी प्रणाली में देरी कितनी लंबी है जहां न्याय त्वरित लेकिन जानबूझकर माना जाता है"।वही आदर्श रहा है

च

व्हाइट, जे. द्वारा यू. एस. बनाम में कहा गया।इवेल, 15 लॉयर्स एडन।2627, निम्नलिखित शब्दों में:

" त्वरित सुनवाई का छठा संशोधन अधिकार अनिवार्य रूप से सापेक्ष है, देरी के अनुरूप है, और इसके आवश्यक अवयवों के रूप में अधिक गति के बजाय व्यवस्थित अभियान है; और क्या इसमें देरी होती है।

जी.

अभियोजन पूरा करना अधिकारों के असंवैधानिक वंचित करने के बराबर है जो सभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

हालाँकि, अत्यधिक लंबे विलंब को पूर्वाग्रह के अनुमानित प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है।इस संदर्भ में, अभियुक्त की कैद का तथ्य भी एक प्रासंगिक तथ्य होगा।अभियोजन पक्ष को उत्पीड़न नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति

ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

379

लेकिन अभियोजन कब अभियोजन बन जाता है, यह फिर से किसी दिए गए मामले के ए तथ्यों पर निर्भर करता है।

7. हम जिसे 'मांग' कहा जाता है, उसे पहचान नहीं सकते या उसे लागू नहीं कर सकते।

नियम।एक अभियुक्त स्वयं पर मुकदमा नहीं चला सकता है; उसके आदेश पर अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाता है

अभियोजन।इसलिए, त्वरित सुनवाई से इनकार करने की अभियुक्त की याचिका को यह कहकर पराजित नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त ने किसी भी समय त्वरित सुनवाई की मांग नहीं की थी।यदि बी के मामले में, उन्होंने ऐसी मांग की और फिर भी उन पर तेजी से मुकदमा नहीं चलाया गया, तो यह उनके पक्ष में एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन केवल त्वरित मुकदमे की मांग न करने को आरोपी के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है।यू. एस. ए. में भी, बार्कर और अन्य सफल मामलों में मांग नियम की प्रासंगिकता काफी कम हो गई है।

8. अंततः, न्यायालय को कई प्रासंगिक सी कारकों-संतुलन परीक्षण 'या' संतुलन प्रक्रिया '-को संतुलित और तौलना होता है और प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करना होता है कि क्या किसी मामले में त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार किया गया है।

9. सामान्य तौर पर, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी आरोपी के त्वरित मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो आरोप या दोषसिद्धि, जैसा भी मामला हो, रद्द कर दी जाएगी।लेकिन यह एकमात्र खुला पाठ्यक्रम नहीं है।किसी मामले में अपराध की प्रकृति और अन्य परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि कार्यवाही को रद्द करना न्याय के हित में न हो।ऐसे मामले में, अदालत के लिए यह खुला है कि वह ऐसा अन्य उचित आदेश दे जिसमें एक निश्चित समय के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का आदेश शामिल है जहां मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है या उस सजा को कम करना जहां मुकदमा समाप्त हो गया है जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और न्यायसंगत माना जा सकता है।

:डी. ए.

ई.

10. परीक्षण के लिए कोई समय-सीमा तय करना न तो उचित है और न ही व्यावहारिक है।

अपराध।ऐसा कोई भी नियम योग्य होने के लिए बाध्य है।इस तरह के नियम को केवल अभियोजन पक्ष के कंधों पर औचित्य साबित करने का बोझ डालने के लिए भी विकसित नहीं किया जा सकता है।त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार करने की शिकायत के प्रत्येक मामले में, एफ

यह मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष पर है कि वह देरी को उचित ठहराए और समझाए।साथ ही, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह शिकायत पर फैसला सुनाने से पहले किसी दिए गए मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करे।यू. एस. ए. के सर्वोच्च न्यायालय ने भी छठे के बावजूद ऐसी कोई भी एफ बाहरी समय सीमा तय करने से बार-बार इनकार कर दिया।

संशोधन।न ही हम यह समझते हैं कि ऐसी कोई बाहरी सीमा तय नहीं करने से त्वरित सुनवाई के अधिकार की गारंटी अप्रभावी हो जाती है।

जी.

1

11. त्वरित सुनवाई के अधिकार से इनकार और राहत के आधार पर आपत्ति

उस कारण से, पहले उच्च न्यायालय को संबोधित किया जाना चाहिए।भले ही ऊँचे

{

न्यायालय ऐसी याचिका पर विचार करता है, आम तौर पर उसे गंभीर और असाधारण प्रकृति के मामले को छोड़कर कार्यवाही पर रोक नहीं लगानी चाहिए।हालाँकि, उच्च न्यायालय में ऐसी कार्यवाही का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

एच 380

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

55. आइए अब हम 1990 की रिट याचिका संख्या 833 में तथ्यों की जांच करें।

क.

उपरोक्त सिद्धांतों का प्रकाश।यह सच है कि 1982 में स्थापित 1982 का विशेष मामला संख्या 24 अभी भी वर्ष 1991 में लंबित है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?जैसे ही विशेष न्यायाधीश (श्री पी. एस. भुट्टा) द्वारा प्रक्रिया जारी की गई, अभियुक्त पेश हुआ और उसने दो आपत्तियाँ उठाईं।:एल (आई) कि विशेष न्यायाधीश को इसका संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

एक निजी शिकायत के आधार पर मामला और यह कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच एक शर्त है-संज्ञान लेने के लिए पूर्ववर्ती; और

((ii) जब तक राज्य सरकार 1952 के अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत अधिसूचना जारी नहीं करती है, तब तक किसी भी विशेष न्यायाधीश के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।

मामले का संज्ञान लेने के लिए।

इन आपत्तियों को समाप्त कर दिया गया-विशेष न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया गया।इसके बाद उन्होंने इस मामले को उच्च न्यायालय में उठाया।उच्च न्यायालय ने भी अपना पहला फैसला सुनाया

आपत्ति की।जहाँ तक दूसरी आपत्ति का संबंध है, डी उच्च न्यायालय के लिए इसमें जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि उच्च न्यायालय में कार्यवाही लंबित थी।

न्यायालय, महाराष्ट्र सरकार ने धारा के तहत एक अधिसूचना जारी की थी

7 (2) 1952 का अधिनियम, श्री सुले को उक्त मामले की सुनवाई के लिए नामित करता है।इसके बाद वे इस मामले को इस अदालत में ले गए, जिसे भी फरवरी, 1984 में खारिज कर दिया गया।इस बीच, उन्होंने श्री सुले के समक्ष इस आशय की एक और आपत्ति जताई थी कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना, उनके खिलाफ अपराधों के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

ई.

सवाल, क्योंकि वे महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे।श्री सुले उनसे सहमत हुए लेकिन इस अदालत ने ऐसा नहीं किया और निर्देश दिया कि मुकदमा दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलना चाहिए।मुकदमे में तेजी लाने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।खत्री, जे. से पहले अभियुक्त ने आपत्ति जताई कि वह मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है।आपत्ति का निपटारा कर दिया गया।वह इस अदालत में आए लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।उस समय, मेहता, जे. ने कुछ आरोप लगाए लेकिन इनकार कर दिया

च

कुछ अन्य आरोपों के संबंध में आरोप तय करना।शिकायतकर्ता इस अदालत में आया और सफल रहा।इसके बाद मामले को जे. शाह ने उठाया, जिन्होंने 79 आरोप बनाए और मुकदमा शुरू किया।कई गवाहों से पूछताछ की गई और 1986 तक भारी सबूत पेश किए गए, जब आरोपी ने इस मामले में संपर्क किया।

आई।

कला के तहत फिर से अदालत।21 और दो S.L.Ps के माध्यम से और 1986 में कार्यवाही G पर रोक लगा दी।

अप्रैल 1988 में, 5 के बहुमत से एक सात न्यायाधीशों की पीठः2 उनसे सहमत थे कि संविधान पीठ द्वारा 16.2.1984 पर दिया गया निर्देश था

अधिकारिता के बिना और यह कि उच्च न्यायालय को उक्त मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता था।परिणाम यह हुआ कि मामले की सुनवाई अब विशेष न्यायाधीश द्वारा की जानी थी।लेकिन कौन सा विशेष न्यायाधीश?शिकायतकर्ता के वकील से पूछता है।

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक (रेड्डी, जे.)

381

श्री सुले, जिन्हें पहले ए के तहत जारी एक अधिसूचना के तहत नामित किया गया था

1952 के अधिनियम की धारा 7 (2) का न्यायाधीश होना बंद हो गया।इस मामले की सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायाधीश को नामित करने वाली कोई अन्य अधिसूचना नहीं थी।धारा 7 (2) के तहत अधिसूचना के बिना, हो सकता है कि बॉम्बे के दो विशेष न्यायाधीशों में से कोई भी इस मामले को उठाने के लिए सक्षम न हो।वास्तव में, यह 1982 में की गई याचिकाकर्ता की आपत्ति थी, जिस पर उच्च न्यायालय या इस अदालत द्वारा बी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को देखते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित होने तक कोई निर्णय नहीं दिया गया था।बंबई उच्च न्यायालय ने भी किसी भी विशेष न्यायाधीश को फाइल नहीं भेजी।यह कि ऐसी अधिसूचना आवश्यक थी, महाराष्ट्र सरकार का भी विचार था, जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सी. आर. एल.) में विद्वान महाधिवक्ता (निर्देशों पर किए गए) के बयान से स्पष्ट होगा। 1990 का सं. 281 का निपटान 23.4.1990 पर किया गया।महाराष्ट्र सरकार ने वास्तव में सी ने 19.6.1990 पर एक विशेष न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में नामित करते हुए अधिसूचना जारी की।

इस मामले का परीक्षण करने के लिए सक्षम।

इस स्तर पर, हमें अर्थ के संबंध में एक विवाद का उल्लेख करना चाहिए

और 1984 (2) एस. सी. आर. 914 में न्यायालय के निर्णय का प्रभाव।श्री P.P.Rao का कहना है कि यह निर्णय, हालांकि स्पष्ट शब्दों में नहीं है, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है!आवश्यक वैध और सक्षम।वे फैसले के अंतिम पैरा पर विशेष जोर देते हैं, जिसका निहितार्थ है कि श्री भुट्टा द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए, विशेष न्यायाधीश

जिसमें लिखा हैः

सभी विभिन्न ई से मामले की जांच करने के बाद

कोण, हम संतुष्ट हैं कि निष्कर्ष दोनों द्वारा पहुँचा गया है

बंबई उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधीश और खंड पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक निजी शिकायत स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य थी और यह कि संज्ञान उचित रूप से लिया गया था, सही है।तदनुसार, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

वाई.

च

श्री राव ने आगे तर्क दिया कि भले ही इसके तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी

1952 के अधिनियम के बावजूद प्रधान विशेष न्यायाधीश के पास उक्त मामले पर विचार करने और उसे आगे बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र था।वह इसे स्वयं आजमा सकते थे या बना सकते थे।

अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश को भेजें।उनका तर्क है कि यह स्थिति इस अदालत के फैसले के बाद आती है कि विशेष न्यायाधीश की अदालत भी मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालत है।

जी.

दूसरी ओर, श्री घाटते का तर्क है कि वहाँ बिल्कुल है

पूरे फैसले में इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं की गई है और अंतिम पैरा को फैसले में चर्चा के आलोक में समझा जाना चाहिए न कि अलग से।हमें इस विवाद पर बोलने की आवश्यकता नहीं है।इस संदर्भ में जो प्रासंगिक है वह यह नहीं है कि वास्तविक कानूनी स्थिति क्या थी।यह है कि क्या कमरा एच 382 था

ए वास्तविक संदेह के लिए और क्या कानूनी स्थिति अस्पष्ट नहीं थी?इस दृष्टिकोण से, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि मामले ने दो रायों को स्वीकार किया और यह कि मुद्दा अस्पष्टता से मुक्त नहीं था।तथ्य यह है कि महाराष्ट्र के महाधिवक्ता, महाराष्ट्र सरकार और दो ने सीखा

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सोचा कि 1952 के अधिनियम के तहत एक अधिसूचना मामले में आगे बढ़ने के लिए 'आवश्यक' थी, यह भी दर्शाता है कि उक्त बी दृष्टिकोण बिना किसी बल के नहीं था।भले ही बॉम्बे के लिए केवल एक विशेष न्यायाधीश होता, फिर भी श्री सुले को इस मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायाधीश के रूप में निर्दिष्ट करने वाली पिछली अधिसूचना को देखते हुए संदेह की गुंजाइश बनी रहती।इसलिए, इस संबंध में श्री घटते के तर्क को निराधार नहीं माना जा सकता है।इन परिस्थितियों में अप्रैल, 1988 और जून, 1990 के बीच की अवधि को शिकायतकर्ता द्वारा की गई देरी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

एस.

यह सच है कि अप्रैल, 1988 में इस अदालत की सात-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद, शिकायतकर्ता ने खुद सरकार का रुख नहीं किया।

महाराष्ट्र ने मामले के लिए एक विशेष न्यायाधीश नामित किया लेकिन दूसरे न्यायाधीश तक इंतजार किया

व्यक्ति, एक वकील, ने ऐसा किया।(बेशक, जब उच्च न्यायालय द्वारा पूछा गया, तो उन्होंने अभियोजन के साथ आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की)।यह भी सच है कि सरकार द्वारा दिनांक 1 की अधिसूचना जारी करने के बाद भी, वह लगभग सितंबर, 1991 तक इस मामले में आगे नहीं बढ़े, लेकिन उनके इस आचरण को निम्नलिखित परिस्थितियों के खिलाफ तौला जाना चाहिएः

" (ए)।जिन अपराधों के लिए अभियुक्त-याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया है, वे काफी गंभीर हैं।79 आरोप तय किए गए थे

ई.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इससे पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर शक्ति के दुरुपयोग के तहत उन लोगों को शामिल किया था।यह सच है कि इस धारणा के साथ जो कुछ भी शून्य हो गया है कि मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना ही अक्षम था।लेकिन उपरोक्त तथ्य उन अपराधों की प्रकृति को दिखाने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है जिनके साथ याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया है और उन्हें आधारहीन नहीं कहा जा सकता है-प्रथम दृष्टया। बॉम बे उच्च न्यायालय का निर्णय (डब्ल्यू. पी. सं. <आई. डी. 2 में, <आई. डी. 1 पर अनुमति दी गई) है, जिसने याचिकाकर्ता को उक्त गतिविधि के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।यह याद रखना चाहिए कि उस रिट याचिका में कई आरोप और यह

च

जी.

आपराधिक मामले आम हैं-इस अदालत के पहले के फैसलों में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है।जनहित सच्चाई जानने में निहित है।(ख) बड़ी मात्रा में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे।उन वर्षों के दौरान बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनके (आर. एस. नायक) द्वारा।57 गवाहों से पूछताछ की गई और 963 दस्तावेजों को पेश किया गया।द.

2

एच. ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक (रेड्डी, जे.)।383

बंबई उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य ए को दर्ज करने में लगभग एक वर्ष बिताया, जो 1200 से अधिक पृष्ठों का था।

:

उन्होंने लगभग अपना पक्ष बंद कर लिया था।इसके लिए उन्हें खर्च के अलावा बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी।अप्रैल, 1988 में इस अदालत के फैसले से यह सब व्यर्थ हो गया।उस साक्ष्य को फिर से पेश करना कोई आसान काम नहीं है।इसलिए, 31.5.1989 पर उन्होंने इस अदालत (सी. एम. पी. संख्या. 1946/90) में एक आवेदन किया कि उस बी साक्ष्य को विशेष न्यायाधीश के समक्ष साक्ष्य के रूप में माना जाए।यह सच है कि हम अब उस आवेदन को खारिज कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अपील उनके द्वारा सद्भावना के अलावा अन्य तरीके से की गई थी और न ही इसे देरी करने की रणनीति कहा जा सकता है।वह आवेदन लंबित रहा।शिकायतकर्ता एक व्यक्ति है।हो सकता है कि वह किसी राजनीतिक दल के सदस्य हों। लेकिन इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है।ग) 1988 तक, यह अभियुक्त ही था जो समय-समय पर कई आक्षेप उठा रहा था और मुकदमे पर रोक लगा रहा था।उनमें से अधिकांश में वह असफल रहे।एक में वह सफल हुए।हम उन्हें पहले ही ऊपर विस्तार से बता चुके हैं और उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।हो सकता है कि कुछ असामान्य घटनाओं के लिए वही प्रणाली आंशिक रूप से जिम्मेदार थी।कॉम-डी के प्रवक्ता निश्चित रूप से दोषी नहीं थे।शिकायत चींटी की निष्क्रियता, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, केवल सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के बाद होती है, न कि उससे पहले।वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका * * * (सी. आर. एल.) 542/86 और एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 2518/86 अभी भी इस अदालत में लंबित हैं, जिसमें वह धारा 197 Cr.P.C के संवैधानिक ई. आई. टी. पर सवाल उठा रहा है और यह भी तर्क दे रहा है कि उसके खिलाफ आरोपों के लिए उसी धारा के तहत मंजूरी की आवश्यकता है।

3 .

घ) अप्रैल, 1988 के बाद इस मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम विशेष न्यायाधीश के बारे में प्रचलित अस्पष्टता और इस मामले को जारी करना।आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम एफ की धारा 7 (2) के तहत अधिसूचना

केवल जून, 1990 में।(वर्तमान रिट याचिका उसी महीने दायर की गई थी)।

' ई) याचिकाकर्ता को कभी जेल नहीं भेजा गया है-एक दिन के लिए भी नहीं।यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है कि इस देरी ने उनके मामले को कैसे प्रभावित किया है।अपनी रिट याचिका के आधार संख्या 10 में, उन्होंने केवल यह कहा कि जिन छह व्यक्तियों से वह मुकदमे में पूछताछ करना चाहते थे, उनकी मृत्यु हो गई है।उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी, नवल टाटा, पेसी टाटा और वसंतदादा पाटिल सहित छह लोगों का नाम लिया है।हालाँकि, उन्होंने यह विस्तार से नहीं बताया कि उनमें से किस पहलू पर जाँच करने का प्रस्ताव था?श्रीमती इंदिरा गांधी और पेसी टाटा की मृत्यु अप्रैल, 1988 से पहले ही हो गई थी।द.

जी.

1 }

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अप्रैल, 1988 के बाद अन्य चार लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एच. आई. नहीं है।

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

384

यह दिखाता है कि कैसे इसने उसे पूर्वाग्रह का कारण बना दिया है।वास्तव में,

क.

श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री वसंतदादा पाटिल दोनों को उद्धृत किया गया था

शिकायतकर्ता के गवाह (क्र. नं. शिकायत में संलग्न गवाहों की सूची में क्रमशः 106 और 114)।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर

बी संतुलन प्रक्रिया-हमारी राय है कि यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।बनाने के लिए उचित दिशा निर्देशित करना है

दिन-प्रतिदिन के आधार पर त्वरित परीक्षण।तदनुसार, हम 1990 की याचिका संख्या 833 को खारिज करते हैं और इस मामले के लिए नामित विशेष न्यायाधीश को इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेने और इसे समाप्त होने तक दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं।एस 56।अब 1987 की रिट याचिका संख्या 268 (रंजन द्विवेदी) पर आते हुए स्थिति यह हैः

}

" हमारे सामने रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष को किसी भी देरी की रणनीति या उस मामले के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि आपराधिक कार्यवाही डी को दिल्ली स्थानांतरित करने की तारीख से मुकदमे के संचालन में कोई देरी हुई है।प्रत्यर्थियों द्वारा हमारे समक्ष रखी गई इस अवधि के लिए अदालत की कार्यवाही स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि इस अवधि के दौरान अभियोजन पक्ष हमेशा मुकदमे को जारी रखने के लिए उत्सुक रहा है।यह कि मुकदमा अब तक समाप्त नहीं हो सका है, उन कारणों से है जिनके लिए अभियोजन पक्ष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।श्री जेठमलानी प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त पुनरीक्षण (सी. आर.) दायर करने के लिए बाध्य था।संशोधन सं. 191/86) दिल्ली उच्च न्यायालय में, वर्ष 1986 में, और प्राप्त करें

ई.

अभियोजन पक्ष द्वारा अपनाए गए अनुचित और अनुचित रवैये के कारण कार्यवाही पर रोक और इसलिए, पांच साल (1986 से 1991) की देरी को अभियोजन पक्ष के दरवाजे पर रखा जाना चाहिए।हम डरते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते।यह कहना एक बात है कि अभियुक्त ने सद्भावना से अपने अधिकारों की रक्षा और पुष्टि करने के लिए उक्त आपराधिक संशोधन दायर किया था और इसलिए, उस पर देरी करने की रणनीति का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।लेकिन यह कहने की एक और बात है कि जब से

च

अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ करने के उनके अनुरोध का विरोध किया था।

अभियोजन पक्ष) अदालत के गवाह के रूप में, इसे इस सभी देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।यह याद रखना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के रुख को विद्वत विचारण न्यायाधीश ने बरकरार रखा था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1979 के बाद से (जब कार्यवाही दिल्ली अदालत में स्थानांतरित की गई थी) अभियोजन पक्ष को गैनी देरी का दोषी नहीं कहा जा सकता है।यह बात व्यावहारिक रूप से विवाद से परे है।

हालांकि, श्री जेठमलानी ने कुछ अन्य दलीलें उठाईं, जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष 1975 से 1979 की अवधि के दौरान इस मामले में कई अवैधताओं और अनियमितताओं का दोषी है जो इसके मालोवो हेलेंस को स्थापित करता है।हमने पैरा 23 (ऊपर) में उक्त तर्कों को निर्धारित किया है।विशेष रूप से उन्होंने

{ ए. आर. एंटूले बनामआर. एस. नायक [रेड्डी, जे.]

385

इस तथ्य पर जोर दिया कि हालांकि याचिकाकर्ता को जुलाई, 1975 में दो मामलों में गिरफ्तार किया गया था

क.

अपराध (मुख्य न्यायाधीश रे की हत्या के प्रयास का मामला और एल. एन. मिश्रा हत्या का मामला) अभियुक्त को कभी सूचित नहीं किया गया कि उसे बाद के अपराध में फंसाया गया है।उन्हें दिसंबर, 1976 तक पटना की अदालत में कभी पेश नहीं किया गया था और समय-समय पर उन्हें पटना की अदालत में पेश किए बिना और उन्हें सूचित किए बिना रिमांड की अवधि बढ़ाई गई थी।उन्होंने बताया कि अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की समाप्ति पर याचिकाकर्ता ने धारा 167 Cr.P.C के तहत रिहा होने का अधिकार बी अर्जित किया था क्योंकि उस अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।अभियुक्त-याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त करने के बाद भी, एल. एन. मिश्रा हत्या मामले में उसके शामिल होने के कारण उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सका।विद्वान वकील का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद कारावास की अवधि अवैध थी।कुछ अन्य कथित अवैधताओं का भी उल्लेख किया गया है।हालाँकि, हम इस रिट याचिका में उक्त पहलू की शुद्धता या अन्यथा पर उच्चारण करना उचित नहीं समझते हैं।यदि वास्तव में, ऐसी कोई अवैधता की गई है, तो हमें विश्वास है कि जब मामला अंतिम निपटारे के लिए आएगा तो अदालत द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।इस संदर्भ में यह प्रासंगिक है।यह ध्यान देने के लिए कि याचिकाकर्ता ने उचित समय पर उक्त अवैधताओं के कारण आरोपों को रद्द करने के लिए नहीं कहा था।हम उक्त आधार पर इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकते हैं-यह मानते हुए कि उक्त आधार वैध और स्वीकार्य हैं, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष ने पांच साल की अवधि में फैले 151 गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपना मामला पूरा कर लिया है।

7

विद्वान वकील, श्री जेठमलानी ने इस तथ्य पर भी बहुत जोर दिया कि सी. बी. आई. दो अरुण कुमारों के खिलाफ अदालत के समक्ष सबूत पेश करने के लिए बाध्य था, जिनके खिलाफ वे लगभग छह महीने से कार्यवाही कर रहे थे और जिनके इकबालिया बयान भी सी. बी. आई. द्वारा दर्ज किए गए थे। विद्वान अटॉर्नी जनरल, हालांकि इस तरह के किसी भी दायित्व पर विवाद करते हैं, लेकिन प्रस्तुत करते हैं कि जांच अधिकारी ने अपने साक्ष्य में इन सभी परिस्थितियों को समझाया है और यह कि अभियुक्त द्वारा उनसे बहुत विस्तार से जिरह की गई थी।उन्होंने कहा कि उनके साक्ष्य 200 पृष्ठों में हैं।विद्वान महान्यायवादी ने इन आधारों को अब इस आधार पर उठाए जाने पर आपत्ति जताई कि रिट याचिका में इन उपबंधों का कोई आधार नहीं है।श्री जेठमलानी के इस निवेदन पर हमें कोई राय व्यक्त करना मुश्किल लगता है क्योंकि यह सीधे तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक पुनरीक्षण में इस तथ्य के अलावा मुद्दा है कि रिट याचिका में ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अपनी वर्तमान विवादित स्थिति में, यह मामले की परिस्थितियों में पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक वैध आधार प्रस्तुत नहीं करता है।

ई.

1

च

जी "।

श्री जेठमलानी ने इस मामले की एक असामान्य विशेषता पर भी जोर दिया, जिसमें सी. बी. आई. और बिहार सी. आई. डी. द्वारा एक दूसरे के खिलाफ झूठे निहितार्थ और साजिश के आरोप और जवाबी आरोप लगाए गए हैं।उनका कहना है कि बिहार एच के अनुसार

[1991] एसयूपीपी।3 एस सी आर।

ए 386

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4

एक सी. आई. डी. सी. बी. आई. आनंद मार्ग के सदस्यों के खिलाफ साजिश रचने का दोषी है, जबकि सी. बी. आई. के अनुसार बिहार सी. आई. डी. जानबूझकर आगे बढ़ रहा है।

असली दोषियों को छोड़ते हुए निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ।लेकिन हम एक ऐसे चरण में हैं जहां अभियोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य पूरा कर लिया है और केवल आरोपी की जांच और बचाव पक्ष के साक्ष्य, यदि कोई हो, की रिकॉर्डिंग बाकी है।बेशक, अगर याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर आपराधिक संशोधन

बी अदालत ऐसे गवाहों की जगह लेती है जिन्हें अदालत द्वारा अनुमति दी जा सकती है, अदालत के गवाहों के रूप में भी पूछताछ की जाएगी।जो भी हो, तथ्य यह है कि मुकदमे का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया है।याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा 13 मार्च, 1978 तक जमानत पर रिहा कर दिया गया है।केवल मामले का उचित निपटारा ही सच्चाई को सामने लाएगा।इस प्रकार, पक्ष और विपक्ष में आने वाली परिस्थितियों पर विचार करने पर, हमारी राय है कि इस स्तर पर आरोपों और/या आपराधिक सी कार्यवाही को रद्द करना उचित और उचित नहीं होगा।इस मामले में उचित आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय से आपराधिक मामलों का निपटारा करने का अनुरोध करना है।

1986 का संशोधन सं. 191 जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः इस आदेश की प्रतिलिपि की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उसे सूचित किया जाता है।आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के निपटारे के बाद, विचारण न्यायाधीश मामले को उठाएगा और डी परिस्थितियों में और अधिमानतः दिन-प्रतिदिन के आधार पर यथासंभव अधिक से अधिक अभियान के साथ आगे बढ़ेगा।

57. 1990 की रिट याचिका संख्या 833 और 1987 की रिट याचिका संख्या 268 को तदनुसार उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज कर दिया जाता है।आपराधिक अपील

पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पी 1 पीठ के फैसले के खिलाफ बिहार राज्य द्वारा 1987 की संख्या 126 को भी पहले के कारणों से खारिज कर दिया गया है।डब्ल्यू. पी. और सीआरएल.याचिका खारिज कर दी गई।

जीएन.